

संक्षिप्त खबरें

राज्य में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध, आदेश जारी

रंजी : झारखंड सरकार ने आज से गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध एक साल के लिए लगाया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड में कैंसर फैलने का सबसे बड़ा कारण गुटखा बना हुआ है। इसकी वजह से युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कैंसर दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट कर दिया था कि राज्य में गुटखा पर प्रतिबंध लगेगा।

26वें सीईसी के रूप में आज शपथ लेंगे ज्ञानेश कुमार

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने और राम मंदिर ट्रस्ट के गठन संबंधी सरकार के कदमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ज्ञानेश कुमार बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) का पदभार ग्रहण करेंगे। कुमार जनवरी 2024 में सहकारिता मंत्रालय में सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए और मार्च 2024 में उन्हें निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। राजीव कुमार के मंगलवार शाम को सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद वह 26वें सीईसी के रूप में शपथ लेंगे। कुमार को सुखबीर सिंह संघू के साथ एक ही दिन निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। दोनों ही 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान आयोग का हिस्सा थे। कुमार, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए बने नए कानून के तहत इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले सीईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी, 2029 तक रहेगा। इसके कुछ दिन पहले निर्वाचन आयोग द्वारा अगले लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने की संभावना है। कानून के मुताबिक सीईसी और निर्वाचन आयुक्तों को 65 साल की उम्र होने या आयोग में छह साल की सेवा पूरी करने में से जो भी पहले हो, सेवानिवृत्त होना पड़ता है।

प्राणराज महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई, दो की मौत

रामगढ़ : रामगढ़ जिले के मांडू थाना क्षेत्र में मंगलवार को प्राणराज महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार खड़े ट्रक में टकरा गई। दुर्घटना में दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर पश्चिम बंगाल के झालदा लौट रहे थे।

सीएम हेमंत सोरेन ने 289 चयनित अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र, कहा शहरी विकास में निभाएंगे अहम भूमिका

बिभा संवाददाता

रंजी : मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्तियों की जा रही है। आज इसी क्रम में नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग झारखंड के अंतर्गत प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित द्वितीय तल सभागार में 289 अभ्यर्थियों की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा गया। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को मंत्री वित्त विभाग राधाकृष्ण किशोर ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों संबोधित करते हुए कहा कि हमें ये विश्वास है कि आप अपने मेहनत से आगे भी कामयाबी हासिल करेंगे। आप संकल्प लें कि व्यवस्था, सिस्टम के किसी भी क्षेत्र में ईमानदारी, निष्ठा के साथ काम करेंगे और सरकार के प्रयासों में सार्थक भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य का निर्माण जिस उद्देश्य के साथ हुआ था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा के



सरकार के जनहितकारी इरादों को साकार करने में आपकी भूमिका खास: सुदित्य कुमार

नगर विकास मंत्री सुदित्य कुमार ने कहा कि आज इस प्रोजेक्ट बिल्डिंग से 289 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आखों में सुनहरी समक लेकर आप उज्वल भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ा रहे हैं। शहरीकरण दिनों दिन तेजी से बढ़ रहा है। बेहतर शिक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से निकल कर शहरों की तरफ आ रहे हैं। शहरों के इन्फ्रास्ट्रक्चर्स को हम मजबूत कर रहे हैं। हम शहरों के विकास के मानकों के आधार पर अपने निकायों को संघालित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज बहुत खुशी का दिन है कि तमाम राजनीतिक झंझावातों को पार करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के बच्चों को नियुक्ति देने में सफल रहे हैं। हेमंत सरकार 2.0 के तीसरे महीने में हमने नियुक्तियों का कार्या शुरू कर दिया है। उन्होंने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को कहा कि नगर विकास मंत्री के तौर पर मेरी भी कुछ अपेक्षाएं आप से हैं। आज आपके लंबे सरकारी जीवन की शुरूआत हो रही है। सरकार के जनहितकारी इरादों को साकार करने में आपकी भूमिका एक अधिकारी और कर्मचारी के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है और आपसे बेहतर सेवाओं की उम्मीद है। आप सिस्टम का एक बेहतर पार्ट बनने आएं हैं।

क्षेत्र में भी कई काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री, ग्रामीण क्षेत्र के विकास में, शहरों के इन्फ्रास्ट्रक्चर्स

को मजबूत करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड को युवाओं का राज्य बनाना



नगर विकास के प्रति सरकार प्रतिबद्ध: मुख्य सचिव

मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने कहा कि नगर के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। राज्य के एक चौथाई आबादी शहरों में निवास करती है। शहरी क्षेत्र राज्य के विकास का चेहरा होता है। निकाय क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर्स की चुनौती है। सड़क, नाली ट्रांसपोर्टेशन की चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आजीविका की तलाश में शहर आते हैं, जिससे शहरों की भौगोलिक संरचना चुनौती के रूप में उभरती है। आप सभी के ऊपर दायित्व है कि शहरों के इन्फ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएं। अर्बन एरिया में टेक्निकल लोगों की आवश्यकता है। पहले झारखंड में टाउन प्लानर की भी नियुक्ति होती थी लेकिन पहली बार सहायक टाऊन प्लानर की नियुक्ति वर्तमान सरकार में हो रही है। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं और पूरी लगन एवं सुनियोजित नतीजे से ऐक्टिव रोल में अपने कार्यों को अंजाम दे और शहरों के विकास में झारखंड सरकार का साथ दें।

चाहते हैं। इसका कड़ी में आज युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। हेमंत सरकार -2.0 में सरकार राज्य के विकास प्रति समर्पित हैं और उनके नेतृत्व में हमलोग कदम बढ़ा चुके हैं। नगर विकास विभाग के प्रधान

सचिव सुनील कुमार ने कहा कि आज खुशी का दिन है। सरकार के द्वारा इस वर्ष नियुक्तियां शुरू हो गई हैं। सरकार के द्वारा निकाय क्षेत्रों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। नगर

हर झारखंडी के चेहरे पर मुस्कान हो, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए: संजय प्रसाद यादव

उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज झारखंड के विकास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ा जा रहा है। उन्होंने अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के विकास में, सभी जन कल्याण के विचारों को सार्थक करने की शपथ लें। हर झारखंडी के चेहरे पर मुस्कान हो, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच झारखंड को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है। युवाओं को रोजगार दिलाना, उनके उज्वल भविष्य की सोच के साथ मुख्यमंत्री की दिशा निर्देश में हमलोग काम कर रहे हैं।

नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत कुल 289 अभ्यर्थियों को दिया गया नियुक्ति पत्र

कार्यक्रम में गार्डन अधीक्षक, भेटनरी ऑफिसर, सेनेटरी एण्ड फूड इंस्पेक्टर, सेनेटरी सुपरवाइजर, राज्य निर्देशक एवं विधि सहायक के पदों पर कुल 289 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। जिसमें गार्डन अधीक्षक के 9, भेटनरी ऑफिसर के 8, सेनेटरी एण्ड फूड इंस्पेक्टर के 12, सेनेटरी सुपरवाइजर के 42, राज्य निर्देशक के 174 एवं विधि सहायक के 44 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। राज्य सरकार लगातार विभिन्न विभागों में नियुक्ति कर रही है। इससे पूर्व नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत कार्यालय पदाधिकारी/सहायक नगर आयुक्त/विशेष पदाधिकारी, सहायक नगर निवेशक तथा लेखा पदाधिकारी सहित सहायक अभियंताओं, कनीय अभियंताओं, स्ट्रीट लाईट इंस्पेक्टर एवं पाईप लाईन इंस्पेक्टर सहित कुल-491 अभ्यर्थियों की नियुक्ति जा चुकी है।

निकाय सहित विभिन्न सेक्टर में प्रतिभावान लोगों की जरूरत है। आप अपना काम तत्परता और पारदर्शिता के साथ करेंगे, ऐसी उम्मीद है। इस अवसर पर मुख्य रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, निदेशक सुडा अमित कुमार, अपर सचिव ज्ञानेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं नवनियुक्त अभ्यर्थी उपस्थित थे।

कैबिनेट: राज्यकर्मियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ता में 7-12 फीसदी वृद्धि

बिभा संवाददाता

रंजी : सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक खेला है। राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ता में सात से 12 फीसदी तक की वृद्धि की है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। छठा केंद्रीय वेतन मान के तहत आने वाले राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों को एक जुलाई 2024 के प्रभाव से 239 फीसदी की जगह 246 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। यानि सात फीसदी की वृद्धि की गई है, वहीं पंचम वेतमान के दायरे में आने वाले



कर्मियों को 443 फीसदी से बढ़ाकर 455 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। यानि 12 फीसदी की वृद्धि की गई है।

कारखाना में शाम में भी महिलाएं कर सकेगी काम

राज्य सरकार ने कारखाना संशोधन विधेयक 2024 के गठन को स्वीकृति दे दी है। ईज ऑफ ड्रूइंग

विजनेस के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के लिए इस विधेयक को मंजूरी दी गई है। इसके तहत महिलाएं अपनी सहमति से कारखानों में शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक काम कर सकेंगीं। वहीं कारखाना संशोधन नियमावली

कैबिनेट के अन्य फैसले

- झारखंड आगनबाड़ी सेविका सहायिका नियमावली में संशोधन की स्वीकृति
- पेंशन विभाग के सात लोगों की सेवा नियमितकरण की स्वीकृति
- झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम ईकाई एमएसएमडी विधेयक 2025 के गठन की स्वीकृति
- बिहार राज्य औद्योगिक विकास

निगम और बीएसडीईएल के बकाया भुगतान के लिए 12 करोड़ 74 लाख 28 हजार 95 रूपए की स्वीकृति

- हजारीबाग के तत्कालीन भूसंरक्षण उपनिदेशक सुनील कुमार की अपील अभावदेन खारिज,
- एसटीएफ में प्रतिनियुक्त उपसमादेष्टा स्वर्गीय राजेश कुमार के आश्रितों को सेवा लाभ देने की स्वीकृति

2023 के प्रस्ताव पर भी सहमति दी गई, इसके तहत फैक्ट्री लाइसेंस का निबंधन शुल्क पुनरीक्षण किया जाएगा। कारखानों के वार्षिक दर्न ओवर और कारखाना बंद होने की सूचना में भी संशोधन किया जाएगा।

सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बाजार मांग के अनुसार नवीनतम तकनीक आखर ऑटोमोबाइल के लिए मनोनीयन के आधार पर मार्केट सुजुकी के साथ एमओयू करने की स्वीकृति दी गई।

राजकीय इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन आज, तैयारी पूरी

बिभा संवाददाता

चतरा। इटखोरी में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का विधिवत उद्घाटन बुधवार यानी 19 फरवरी को किया जाएगा। उद्घाटन समारोह को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चतरा उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया कि राजकीय महोत्सव का विधिवत उद्घाटन झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद मंत्री सुदित्य कुमार करेंगे। विधेय अतिथि के रूप में चतरा सांसद कालीचरण सिंह, सिमरिया विधायक उज्ज्वल कुमार दास व चतरा विधायक जनार्दन पासवान उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में धर्मगुरु स्वामी रविंद्र कीर्ति हस्तिनापुर,

झारखंड राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष ताराचंद्र जैन, बोधगया मंदिर समिति के सदस्य सचिव नांगेय दोरजी भी उपस्थित रहेंगे। इस बार तीन दिवसीय महोत्सव में स्थानीय नागपुरी और बॉलीवुड के कई नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। उपायुक्त ने बताया कि तीन दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव के भव्य आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महोत्सव में राष्ट्रीय पटल पर इटखोरी का पुरातात्विक महत्व विषय पर संगोष्ठी का भी विशेष आयोजन किया जाएगा। जिसमें कई प्रसिद्ध वक्ता अपना विचार रखेंगे। आम लोगों की सहभागिता को लेकर जिला प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रही है।

स्पीकर रवींद्र नाथ महतो ने उच्चस्तरीय बैठक में कहा- विभाग समय पर अपने जवाब रखें तैयार

बिभा संवाददाता

रंजी : विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने आगामी बजट सत्र की तैयारियों को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग समय पर अपने उत्तर तैयार रखें, ताकि विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही और सटीक जवाब दिया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा न हो कि किसी प्रश्न का उत्तर किसी अन्य विषय से संबंधित हो। बैठक में राज्य में विभिन्न संगठनों द्वारा किए जाने वाले विरोध-



प्रदर्शनों और घेराव को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए, विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि विधि-व्यवस्था को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी दल को इससे परेशानी हो

रही है, क्योंकि आमतौर पर विपक्षी दलों को नेता प्रतिपक्ष ही संगठित और संघालित करता है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। इस बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह सचिव, डीजीपी, विभिन्न विभागों के सचिव, रंजी एसएसपी और रंजी डीसी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

आधी रात को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना मोदी-शाह की असम्यता : राहुल

एजेंसी

नई दिल्ली : लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आधी रात को नये मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सबको चौंकाया ही नहीं है बल्कि असंवैधानिक कदम उठाकर असम्य होने का भी परिचय दिया है। श्री गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सोमवार को हुई बैठक में

अपनी असहमति यह कहते हुए व्यक्त की थी कि समिति से देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाना गलत है और उनकी जगह गृहमंत्री अमित शाह को समिति में रखना अनुचित है। यह मामला न्यायालय में है और बुधवार को इस बारे में उच्चतम न्यायालय को फैसला देना है इसलिए इस मुद्दे को 19 फरवरी तक स्थगित किया जाना चाहिए लेकिन सरकार ने उनकी असहमति पर ध्यान दिए बिना आधी रात को नये चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी और इस कदम को सभ्य नहीं कहा जा सकता है।

भारत कतर के बीच बनी रणनीतिक साझीदारी, व्यापार होगा दोगुना

एजेंसी

नई दिल्ली : भारत एवं कतर ने अपने दोपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत करते हुए आपसी व्यापार को पांच साल में दो गुना करने, भारत में कतर निवेश केन्द्र खोलने जाने तथा भारत एवं कतर के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने की आज घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच यहां हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय शिखर बैठक में ये निर्णय लिये गये। दोनों देशों ने वैश्विक एवं क्षेत्रीय भूजनीतिक मामलों पर भी विचार विमर्श किया जिनमें हमसा एवं इजरायल



के बीच संघर्ष तथा अफगानिस्तान के मुद्दे भी शामिल थे। कतर के अमीर की राजकीय यात्रा के दौरान दो समझौतों और 5 समझौता ज्ञानों पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें एक- द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत करने तथा दूसरा- दोहरे कराधान

से बचाव संबंधी करार शामिल है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में सचिव (कांउसलर, पासपोर्ट, वीसा एवं प्रवासी भारतीय मामलों) अरुण कुमार चटर्जी ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी में ऊर्जा,

व्यापार एवं निवेश तथा सुरक्षा के क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा दोनों देशों ने बुनियादी ढांचे, बंदरगाह, जहाज निर्माण, फूड पार्क, नवीकरणीय ऊर्जा, रोबोटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जतायी है। उल्लेखनीय है कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने आखिरी बार मार्च 2015 को भारत का दौरा किया था। जब प्रधानमंत्री श्री मोदी ने फरवरी 2024 में अपनी दूसरी यात्रा की, तो उन्होंने कतर के अमीर को भारत की राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। कतर के अमीर के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है

जिसमें प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारिक नेता शामिल हैं। कतर के अमीर का भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री श्री मोदी की मौजूदगी में आज सुबह राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत किया गया। राष्ट्रपति आज शाम को कतर के अमीर से मिलेंगीं और प्रतिनिधिमंडल के साथ अमीर के सम्मान में एक भोज का आयोजन भी करेंगीं। प्रधानमंत्री मोदी और अमीर के बीच हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक व्यापार संबंधों, लोगों के बीच गहरे संबंधों और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को याद किया।

श्री चटर्जी ने कहा कि अपने द्विपक्षीय रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने के लिए, भारत और कतर ने आज इस संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। व्यापार, निवेश और ऊर्जा आज दोनों नेताओं के बीच चर्चा के प्रमुख विषयों में से थे। आज भारत और कतर के बीच सालाना लगभग 14 अरब डॉलर का व्यापार होता है। दोनों पक्ष अगले 5 वर्षों में इसे दोगुना करने का लक्ष्य तय करने पर सहमत हुए हैं। कतर भारत में निवेश के लिए भी एक महत्वपूर्ण भागीदार है। कतर के संयुक्त कृषि, कतर निवेश प्रशिक्षण क्व वर्तमान में भारत में लगभग 1.5 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) है।

संक्षिप्त खबरें

रक्षा राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में डॉ० शरीन से मुलाकात

रांची (बिभा)। आज रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ० एस०के० शरीन और उनकी टीम से मुलाकात की। इस दौरान अस्पताल के डॉ० बी०बी० रेचारी और डॉ० कनिका कौशल भी मौजूद रहे। इस मुलाकात में रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने लिवर रोग विशेषज्ञ श्री शरीन से रांची में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और उसे बेहतर बनाने पर चर्चा की। प्रमुख रूप से रांची में बढ़ती फैटी लीवर और इससे जुड़ी अन्य समस्याओं पर चर्चा हुई। रक्षा राज्य मंत्री ने डॉ० शरीन और उनकी टीम से आग्रह किया कि रांची में एक स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए ताकि फैटी लीवर और उससे जुड़ी बीमारियों से लोगों का बचाव हो सके। रक्षा राज्य मंत्री की प्रस्ताव पर उन्होंने सहमति दी और कहा कि बहुत जल्द ही रांची लोकसभा क्षेत्र की जनता को निःशुल्क स्कैनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस मुलाकात में रक्षा राज्य मंत्री और डॉक्टर शरीन ने भी फैटी लीवर की बढ़ती समस्या पर चिंता जताई और उसके रोकथाम के उपायों पर भी चर्चा की। मुलाकात के बाद रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने कहा कि रांची में फैटी लीवर की समस्या कम हो सके। लोग स्वस्थ हो, इसके लिए डॉक्टर शरीन ने गंभीरता दिखाई है। बहुत जल्द ही उनकी टीम रांची के लोगों की स्कैनिंग की व्यवस्था करेगी ताकि लोग स्वस्थ रहें और यदि कोई समस्या हो तो उसका समय पर उपचार हो सके।

करा पुलिस ने बच्चे के चोट लगे आँख का ईलाज कराकर विवाद सुलझाया

खूँटी (बिभा)। करा प्रखंड के आटा गाँव निवासी गुड्डू मुंडा का छह वर्षीय बेटा प्रकाश तिकी का आँख में खेलेने के दौरान किसी अन्य बच्चे द्वारा चोट लग गया था। जिसका मामला करा थाना तक पहुँचा। जिससे दो पक्षों में विवाद उत्पन्न हो गया था। जिसके बाद पहले बच्चे का ईलाज जरूरी समझ कर पुलिस ने उपचार के लिए रिम्प भेजा। जहाँ बच्चे का आँख ठीक हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब तीन माह पहले दो बच्चे के आपसी खेल-खेल में एक छह वर्षीय बच्चा का आँख में चोट लग गया था जिससे बच्चे का आँख दिखाई देना बंद हो गया था और दो परिवार के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था। ईलाज के बाद बच्चे का आँख का रौशनी वापस लौट गया। जिससे खुश होकर परिजन बच्चे के साथ करा थाना पहुँचे। तभी करा थाना के सब इंस्पेक्टर जोगेश सिंह और चौकीदार विनोद कुमार महतो ने दोनों पक्षों विवाद का खत्म कराया और आपसी भाई चारे के साथ गाँव में रहने की बात कही।

महाशिव रात्रि पुजा को लेकर तैयारी जोरों पर

खूँटी (बिभा)। करा प्रखंड में महाशिवरात्रि पुजा को लेकर सभी शिवालयों को सफाई एवं रंग शोणन किया जा रहा है। सभी शिव भक्त भगवान शिव का बारात में शामिल होने के लिए आतुर। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी करा थाना प्रांगण स्थित मंदिर में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पुजा को लेकर तैयारियाँ जोर-जोर से चल रही हैं। सभी कोई महाशिवरात्रि की तैयारी में जुटे हुए हैं। करा थाना प्रभारी मनीष कुमार ने कहा कि महाशिवरात्रि पुजा महोत्सव के अवसर पर सभी भक्तगणों एवं महाअनुभव को सादर आमंत्रण देते हुए कहीं की 26 फरवरी दिन बुधवार को प्रातः 9 बजे सुबह पूजन एवं रुद्राभिषेक, अपहरण 3 बजे प्रसाद एवं भंडारा, संघ्या 6 बजे भगवान शिव शंकर का बारात प्रस्थान रात्रि में शिव पार्वती विवाह महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर आप सभी महानुभावों एवं भक्तगणों को स्वागत करेगा।

पुलिस ने तीन लोगों को अफीम खेती करने के जुर्म में किया गिरफ्तार

खूँटी (बिभा)। अफीम का अवैध खेती करते हुए जिला केन्द्र के खूँटी पुलिस ने रौहाथ तीन लोगों को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। खूँटी क्षेत्रांतर्गत ग्राम तारो, जिलिंगा, कासीकेला के आस-पास के जंगली क्षेत्रों एवं खेतों में अवैध रूप से पोस्ता / अफीम का खेती की गयी है एवं उक्त अफीम के खेत में अफीम किसान पानी पटवन / घास निकालने का काम कर रहे हैं तत्काल छापाकारी करने से खेती करते हुए किसानों को रोग हाथों पकड़ा जा सकता है, उक्त सूचना के आधार पर वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए आदेशानुसार त्वरित कार्यवाई करते हुए खूँटी थाना क्षेत्र तारो, जिलिंगा, किस्कीकेला में बारी बारी से छापाकारी किया गया। छापाकारी के क्रम में ग्राम तारो से गोमया उरांव पिता बिरसा उरांव ग्राम जिलिंगा से सुखराम मुण्डा पिता मंगु मुण्डा ग्राम किस्कीकेला से दिपक नाग पिता खेला नाग को पोस्ता / अफीम के खेत में पानी पटवन करते हुए रोग हाथों पकड़ा गया जिसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। इस छापाकारी दल में पु०नि० सह थाना प्रभारी मोहन कुमार, पु०अ०नि० मणीदीप कुमार, पु०अ०नि० जितेन्द्र कुमार, पु०अ०नि० अरुण कुमार, पु०अ०नि० अमीत कुमार माडी सहित खूँटी थाना के सशस्त्र बल शामिल थे।

बाल मजदूरी उन्मूलन हेतु जागरूकता अभियान का सफल आयोजन

खूँटी (बिभा)। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निदेशानुसार अखिल भारतीय बचाव पुनर्वास अभियान 2.0 के तहत बाल मजदूरी उन्मूलन हेतु जागरूकता अभियान का आयोजन जनवरी से मार्च 2025 तक किया जा रहा है। इसी क्रम में आज श्रम अधीक्षक, खूँटी एवं जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि यदि कोई व्यक्ति बाल श्रम में दोषी पाया जाता है, तो उसे 50,000 रुपये का जुमाना तथा छह माह की सजा या दोनों हो सकते हैं। इस अवसर पर सभी दुकानदारों, रेस्टोरेंट एवं होटल संचालकों को जागरूक किया गया कि बाल मजदूरी कानूनी अपराध है और इससे बचना आवश्यक है। जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की कि वे बाल मजदूरी के किसी भी मामले की सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन या संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें।

कृषि पाठशाला में लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं : शिल्पी नेहा

कृषि पाठशाला के लिए चयनित बेड़ों की एजेंसी को टर्मिनेट करने का निर्देश

राज्य की कृषि पाठशाला कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का दर्पण

बिभा संवाददाता

रांची : कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिकी ने समेकित बिरसा विकास योजना सह कृषक पाठशाला की आज नेपाल हाउस में समीक्षा बैठक हुई . समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिकी कृषि पाठशाला के लिए चयनित एजेंसी को सुस्ती को लेकर नाराज दिखाई . राज्य में फिलवक्त 57 एजेंसी कृषि पाठशाला के लिए



चयनित है . कृषि पाठशाला उद्देग हेतम सोरेन की ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है . 25 से 27 एकड़ भूमि पर कृषि पाठशाला के निर्माण में जहाँ कुछ एजेंसियाँ बेहतर काम कर रही हैं जबकि कई एजेंसियों को पहले भी शो कॉज किया जा चुका है . मंत्री शिल्पी नेहा तिकी ने साफ

शब्दों में कहा कि इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी . कृषि पाठशाला में बेड़ों के लिए चयनित एजेंसी को टर्मिनेट करने का निर्देश दिया गया है . एजेंसी को काम में लापरवाही और सुस्ती के लिए पहले ही शो कॉज किया गया था . बावजूद इसके कोई

पत्नी के साथ ससुराल से लौट रहे युवक की अपराधियों ने गला रेतकर की हत्या

बिभा संवाददाता

खूँटी । जिले के करा थाना क्षेत्र में अपराध का मामला धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। कभी हत्या तो कभी रेफ तो कभी बालू तस्करी। वहीं इसी क्रम में सोमवार की रात अपराधियों ने एक आदिवासी युवक को उसके पत्नी के सामने ही गला काटकर हत्या कर दी। यह मामला करा थाना क्षेत्र के राँची कमडारा मार्ग पर छाता नदी के निकट पर घटी। जिसमें राँची के रातु थाना क्षेत्र के सांडील गाँव निवासी 31 वर्षीय सदीप टोपो को कार से उतारकर लोगों ने गला काटकर हत्या कर दी। सदीप टोपो अपने ससुराल कमडारा तेरती गाँव से अपनी पत्नी के साथ अपना घर लौट रहे थे। वहीं हथियारों ने सदीप को कार को पहले रुकवाया फिर उसे गाड़ी से नीचे उतारा और गला रेत कर हत्या कर दी और घटना के बाद पत्नी को वहीं छोड़ दिया। घटना की जानकारी पुलिस को लगी तो फिर करा पुलिस घटनास्थल पर पहुँची और फिर शव को करा थाना ले आयी है। वहीं केस दर्ज किया जा रहा है। वहीं करा पुलिस ने हत्या का सुराग के लिए खोजबीन शुरू कर दी है। वहीं पुलिस कई तरह से



खोजबीन कर कर रही है। ताकि हत्या के कारणों का भी पता चल सके। मृतक का भांजा प्रकाश तिकी ने बताया कि सदीप टोपो अपनी सास को अपना ससुराल छोड़ने पत्नी के साथ गया हुआ था। फिर पत्नी के साथ वापस अपना गाँव लौट रहे थे। जिसकी हत्या योजनाबद्ध तरीके से कर दी गयी। वहीं उन्होंने हथियारों और हत्या में साजिश रचने वाले को पुलिस जल्द से जल्द सजा देने की मांग की है। पवन उरांव ने बताया कि उसकी माँ मामी को लेकर वापस अपना गाँव आ रहे थे तो देर रात उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन मामी रात को ही इसी के साथ मायके चली गई थी। मामा एलंबर का काम करते थे और मामी विद्यालय की टीचर थी एक वर्ष पहले शादी हुआ है लेकिन बाल बच्चे नहीं है।

भारतीय रेशम उद्योग में केंद्रीय रेशम बोर्ड का अप्रतिम योगदान: पी शिवकुमार



बिभा संवाददाता

रांची : पी शिवकुमार सदस्य सचिव केंद्रीय रेशम बोर्ड के कुशल मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिल्व्कटेक 2025 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम के तकनीकी सत्र-2 की अध्यक्षता डा एन बी चौधरी निदेशक सीएसबी-सीटीआरटीआई रांची ने किया। डॉ. हारुन वेंकटेश्वर, सहायक प्रोफेसर,

बाघवार एकेडमी का 19वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से संपन्न

बिभा संवाददाता

चान्हो : प्रखण्ड स्थित मंगलवार कोइ बाघवार एकेडमी में 19वें वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें संस्कृति, कला और शिक्षा का शानदार संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉ. भूपेश कुमार (प्राचार्य, आईएचएम), विद्यालय निदेशक अशोक बाघवार और प्राचार्य अशोक बाघवार द्वारा दीप प्रचलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि का स्वागत विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा पारंपरिक नागपुरी नृत्य से किया गया, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यालय निदेशक अशोक बाघवार ने अपने स्वागत भाषण में कहा,



हमारी आदतें ही हमें महान बनाती हैं। इसलिए हमें अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए और इसकी शुरुआत शिक्षकों एवं अभिभावकों को करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं, जो वे देखते हैं। मुख्य अतिथि डॉ. भूपेश कुमार ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में कहा, हर बच्चा समान क्षमता रखता है, सफलता के लिए स्थान

कोई बाधा नहीं है। विद्यालय ही वह स्थान है, जहाँ बच्चों को हार्संस्कार और संस्कृतिहृ की शिक्षा मिलती है। इसके बाद विद्यार्थियों ने रांगरंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दीं। विद्यार्थियों की सृजनात्मकता, सामाजिक संदेशों से भरपूर प्रस्तुतियों और ऊर्जा से परिपूर्ण प्रदर्शन को अभिभावकों और अतिथियों ने खूब सराहा।

सरना आवासीय उच्च विद्यालय फोरलेन कोटार में आदिवासी कुड़मी समाज की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न

बिभा संवाददाता

खलारी। आदिवासी कुड़मी समाज की केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्यों की एक आवश्यक बैठक सरना आवासीय उच्च विद्यालय फोरलेन कोटार में केंद्रीय उपाध्यक्ष निरंजन महतो की अध्यक्षता में हुई। और संचालन केंद्रीय सचिव वैजनाथ महतो ने की। बैठक में समयाभाव के वजह से केंद्रीय अध्यक्ष प्रसेनजीत महतो के इस्तीफा देने, केंद्रीय महा अधिवेशन करने आयोजन करने, कुड़मालि भाषा के विकास गहन रूप से कैसे हो तथा संगठन में युवाओं की भागीदारी एवं सुचारु पूर्व संचालक कैसे हो, अन्याय। सर्वसम्मति से की वर्तमान अध्यक्ष का इस्तीफा स्वीकार कर तत्कालीन केंद्र उपाध्यक्ष को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। तथा आगामी केंद्रीय



अधिवेशन मार्च महीने तक करने का निर्णय लिया गया साथ ही युवाओं को जोड़ने के लिए स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक संगठन कुड़मालि भाषा के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय कार्यकारिणी सलाहकार चंद्रनाथ भाई पटेल एवं प्रेम प्रकाश महतो ने बारी-बारी से सभी लोगों की बातों को सुनकर अपना निर्णय

सुनाया। तत्पश्चात केंद्रीय कोषाध्यक्ष गणेश्वर महतो ने संगठन सुचारु रूप से आगे कैसे बढ़ेगा उसे पर अपना विचार रखें जिसका सभी लोगों ने सहमति जताई। केंद्रीय सहायक सह केंद्रीय प्रवक्ता रूपलाल महतो ने केंद्रीय सत्यानारायण महतो ही करने का प्रस्ताव दिया। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष पन्नालाल राम ने कहा कि संगठन किसी व्यक्ति पर केंद्रित न

होकर सामूहिकता पर बोल देगा। वहीं पर महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष सोनी देवी ने कहा कि कोई भी घटना इसान को एक नई सीख देती है इसलिए हमें हर घटना पर एक नई सीख के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वहीं पर केंद्रीय महिला सचिव पद्मश्री छुटनी महतो ने महिला शक्ति को आगे लाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देगी और संगठन की मजबूती के लिए महिलाओं को अपना पूर्ण सहयोग देगी। वहीं पर आमंत्रित सदस्य एवं कुरमाली भाषा विशेषज्ञ सुरेश कुड़मी ने जन जन तक कुड़मालि भाषा कैसे पहुंचेगा इस पर अपनी विचार रखें। साथ ही प्रसिद्ध कवि एवं लेखक शंकर लाल बसरीवार ने कुड़मालि गीत गाकर लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से

प्रदेश कोषाध्यक्ष लाल बहादुर चौधरी प्रदेश सहायक दिवाकर प्रसाद प्रदेश सहायक कौशिक जी चतरा जिला प्रभारी महेश महतो बोकारो जिला अध्यक्ष आनंद सागर गोड्डा जिला अध्यक्ष विनोद कुमार महतो सरायकेला खरसावा जिला अध्यक्ष मनोज कुमार महतो रामगढ़ जिला अध्यक्ष शंकर लाल प्रसाद महिला मोर्चा रामगढ़ जिला अध्यक्ष दुलारी देवी पश्चिम सिंहभूम प्रभारी दिनेश कुमार महतो के अलावा दीपक कुमार महतो रीना देवी संतोषी देवी कालेश्वर महतो मनगोविंद महतो टेकलाल महतो धुवनेश्वर महतो राजीव कुमार सत्यानारायण महतो सहित राजेश्वर महतो भूपेंद्र महतो सहित सैकड़ों सक्रिय लोगों ने भाग लिया।

एक नाबालिग निर्दोष बच्चे को बाल मित्र थाने में पिटाई करने पर एसपी ने एएसआई को किया निलंबित

बिभा संवाददाता

खूँटी । जिले के बालमित्र थाना में एक नाबालिग बच्चे की पुलिस द्वारा बेहमी से पिटाई करने का मामला सामने आने के बाद एसपी अमन कुमार ने पिटाई करने के आरोपी एएसआई को निलंबित कर दिया है। जो कि करा थाना क्षेत्र अन्तर्गत एक आरोपी युवक को पकड़ने उसके घर गयी पुलिस ने आरोपी के नहीं मिलने पर उसके नाबालिग बेटे को खूँटी बाल मित्र थाना लाकर पिटाई किया गया था। जिसमें नाबालिग बच्चे को बिना दोष का इतना पिटाई कर दिया गया कि वह चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। दोष पिता का और बेटे को मिली सजा। जो कि करा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने गाँव की एक बच्ची को दिल्ली ले गया है। लेकिन उसने बच्ची को कहाँ ले गया इसका कोई पता नहीं। वहीं आरोपी युवक का दो पत्नी रह रहे आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को फंसाने के ख्याल से गलत संदेश उछला गया। जिसके बाद से पहली पत्नी ने सभी बाँतों के पुलिस से सामने रख दी। वहीं दिल्ली में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहे आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने नाबालिग बेटे को लाकर खूँटी थाने में पिटाई करने का मामला बताया जा रहा है। जिसमें बच्चे के शरीर में मार का दग स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहीं समाजसेवी लक्ष्मी बाखला ने बताया कि

बालक को एक कैदी की तरह रखने का बात बतलाया गया था। उन्होंने बताया कि वहीं उस बालक को हथकड़ी भी पहनाया गया था। जबकि जुबैनाईल एक्ट में ये सब क्रिया एक बच्चे के साथ नहीं करना है। लेकिन इस प्रकार उसके साथ अपभ्रता किया किया गया। इसके बाद पीड़ित बच्चे को सदर अस्पताल खूँटी लाया गया जहाँ उसका उपचार कराया गया। जिसमें एम्बोल्ट बाई पर्सन का उपचार किया गया। तदोपरत बाल संरक्षण विभाग खूँटी के समक्ष पीड़ित बालक को प्रस्तुत कर बचान दर्ज कराया गया। जिसमें स्पष्ट पिटाई की बात कही गई है। जिसपर बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष तनुशी सक्सेर ने इसपर बताया कि बच्चे को मारना तो दूर की बात लेकिन उसके साथ अमानवीय व्यवहार करना भी अपराध है। वहीं बच्चे के शरीर पर स्पष्ट चोट का निशान है जिसे मार गया है। एसपी अमन कुमार ने बताया कि पीड़ित के बचान पर बाल मित्र थाने के एएसआई पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया है। और आगे की कार्यवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पीड़ित बच्चों के पिताजी करा थाना क्षेत्र से एक बच्ची को काम दिलाने के नाम पर गायब कर दिया है जिसे पता चला था कि बच्चों को उसके पिता के एड्रेस के बारे में पता था। तो उसे थाना लाया गया था लेकिन बच्चों को पिटाई करना गैर कानूनी है।

राज्यपाल से 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम के तहत गोवा से आए शिक्षाविदों ने की भेंट



बिभा संवाददाता

रांची : राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मंगलवार को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम के तहत गोवा से आए शिक्षाविदों ने राज भवन में भेंट की। विदित हो कि ये शिक्षाविद रांची विश्वविद्यालय, रांची के शैक्षणिक भ्रमण पर आए हुए हैं। राज्यपाल ने शिक्षाविदों से संवाद के क्रम में राज्य में उच्च शिक्षा को और गुणात्मक व प्रभावी बनाने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा मिले, ताकि वे प्रतिस्पर्धा के इस युग में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि वे

शैक्षणिक मानकों के अनुपालन और सर्वोत्तम के नियमितीकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ प्रयास कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और समाजोत्थान का आधार भी है। उच्च शिक्षा संस्थानों को ऐसा वातावरण विकसित करना चाहिए, जहाँ शोध, नवाचार और मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को समासामयिक चुनौतियों से निपटने के लिए अस्कादमिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक दक्षताओं से भी संपन्न किया जाना आवश्यक है।

विद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन को उप-प्राचार्य अजय उरांव ने प्रस्तुत किया, जिसमें विद्यालय की शैक्षिक उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम का समापन वरिष्ठ शिक्षक हरे कृष्ण सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम का सफल संचालन अंजल कुमारी, मानसी कुमारी, अंजना, प्रिथि और सिफा नाज ने किया। अभिभावकों को यह एहसास हुआ कि बाघवार एकेडमी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नैतिक मूल्यों और समग्र विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ा रही है।

अवैध अफीम की खेती छोड़ वैकल्पिक खेती अपनाने हेतु जागरूकता अभियान

खूँटी (बिभा) । खूँटी प्रखंड के सिलादोने समेत अन्य क्षेत्रों में नुकड़ नाटक के माध्यम से अवैध अफीम की खेती के दुष्प्रभावों से आमजन एवं किसानों को अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को अवैध खेती को छोड़कर वैकल्पिक एवं लाभकारी फसलों की ओर प्रेरित करने का प्रयास किया गया। नुकड़ नाटक के माध्यम से बताया गया कि अवैध अफीम की खेती ने केवल कानूनी अपराध है, बल्कि यह समाज और स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। किसानों को समझाया गया कि वे अफीम की खेती को छोड़कर ड्रैगन फ्रूट, टमाटर, बैंगन, मूंग, इत्यादि जैसी लाभकारी फसलों की खेती करें, जिससे उनकी आजीवनिक भी सुरक्षित रहे और समाज में सकरात्मक बदलाव आए। इस दौरान किसानों को जागरूक करने हेतु पम्पलेट का भी वितरण किया गया।

संक्षिप्त खबरें

राज्यपाल से अबुआ अधिकार मंच का शिष्टमंडल ने की मुलाकात



रांची(बिभा) : राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से अभिषेक कुमार झा के नेतृत्व में अबुआ अधिकार मंच का शिष्टमंडल ने राज भवन में भेंट की। शिष्टमंडल ने राज्य में झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद रिक्त होने की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की दिशा में आवश्यक पहल करने का आग्रह किया। साथ ही, शिष्टमंडल ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की समस्या से भी राज्यपाल महोदय को अवगत कराया।

राज्यपाल से झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का शिष्टमंडल ने की मुलाकात



रांची(बिभा) : राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से पुष्कर महतो के नेतृत्व में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के शिष्टमंडल ने राज भवन में भेंट की तथा विभिन्न विषयों से संबंधित एक ज्ञापन समर्पित किया।

बेरोजगार युवा जुमलेबाजी नहीं अपना हक और अधिकार चाहते हैं : बाबूलाल मरांडी

रांची(बिभा) : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एम पी मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा निशाना साधा। श्री मरांडी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री हेमंत ने कुछ 100-200 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा, करोड़ों रुपये खर्च कर भव्य आयोजन किया गया। हेमंत जी के चाटुकारों द्वारा सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले मुख्यमंत्री का ढोल भी पीटा जाएगा। लेकिन झारखंड के लाखों बेरोजगार युवाओं के कुछ सवाल हैं, जो अब भी अनसुलझे हैं। श्री मरांडी ने पूछा कि प्रतियोगी परीक्षा कैलेंडर कब जारी होगा जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कब होगी, जेएसएससी, सीजीएल पेपर लोक की जांच कहाँ तक पहुँची। मरांडी ने पूछा कि मुख्यमंत्री जी बताएँ किस नियोजन नीति के तहत नियुक्तियाँ कर रहे हैं? झारखंड के युवाओं को कितना आरक्षण दिया गया? उन्होंने कहा कि हेमंत जी, युवाओं का भविष्य पीआर स्टैंड और दिखावों से नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही से संभरेगा। झारखंड के लाखों बेरोजगार युवा जुमलेबाजी नहीं, बल्कि अपना हक और अधिकार चाहते हैं।

झारखंड में आतंकवाद की पाठशाला न लगने दे हेमंत सरकार : प्रतुल शाह देव

रांची(बिभा) : भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने हेमंत सरकार से मांग की है कि वह झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवाद की पाठशाला न लगने दे प्रतुल ने उस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त किया जिसमें खुफिया तंत्र ने बताया कि पाकुड़ में बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का एक दुरात आतंकवादी अखुल मनुन बांग्लादेश बांग्लादेश सीमा को पार कर पाकुड़ पहुँच गया था। इसने वहाँ दर्जनों स्थानीय युवकों को ट्रेनिंग दी थी। प्रतुल ने कहा यह बहुत ही गंभीर मामला है जब आतंकवादी झारखंड में आतंकवाद की पाठशाला लगा रहे हों और उनके जाने के बाद राज्य के खुफिया तंत्र को इसकी खबर लगती है। प्रतुल ने कहा राज्य सरकार को अतिवर्ध इस मुद्दे पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर जो लोग मदद कर रहे हैं उन पर भी कानून का शिकंजा कसे।

सदर अस्पताल से नवजात की चोरी, पुलिस ने शुरु की जांच

रांची(बिभा) : राजधानी के सदर अस्पताल से नवजात बच्चे की चोरी का चौकाने वाला मामला सामने आया है, घटना सोमवार शाम करीब 7:30 बजे की है, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी मंगलवार सुबह हुई। लोअर बाजार थाना पुलिस ने थाना प्रभारी दयानंद कुमार की देखरेख में मामले की जांच शुरू कर दी है। पिठोरिया के उमेश बेदिया के घर पांच दिन पहले जन्मी बच्ची की देखभाल उसके परिजन अस्पताल में कर रहे थे, खबरों के मुताबिक, सोमवार की रात जब नवजात रोने लगा तो परिजन टहलने के बहाने अस्पताल से बाहर निकल गये, बाहर रहते हुए, वे एक महिला से बातचीत करने लगे जिसने अवसर का लाभ उठाकर बच्चे को चुरा लिया। जब माता-पिता को पता चला कि उनकी बेटी लापता है तो वे सदमे में आ गए। बच्चे के पिता उमेश बेदिया ने लोअर बाजार थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायी है, अधिकारी इलाके के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर रहे हैं और अधिक जानकारी जुटाने और चोरी में शामिल महिला की पहचान करने के लिए परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रहे हैं।

महाशिवरात्रि की तैयारियों का जायजा लिया पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुबोधकांत सहाय

रांची (बिभा) : महाशिवरात्रि के शिव वारात को भव्य और विशाल बनाने के लिए श्री शिव वारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर के मुख्य संरक्षक श्री सुबोधकांत सहाय, कर्क के विधायक सुरेश बैठा, संयोजक दीपक लाल, संरक्षक कुमार राजा महाशिवरात्रि के अवसर पर निकलने वाले भव्य और विशाल झांकियों का जायजा लिए एवं उसके मांगों को देखा, साथी इस वर्ष इसे और भव्य और विशाल बनाने पर चर्चा किया गया सबसे पहले महासमिति के अध्यक्ष राजेश साहू के द्वारा अंग वस्त्र एवं पहाड़ी बाबा का प्रतीक चिन्ह देकर पहाड़ी मंदिर मुख्य द्वार पर श्री सुबोधकांत सहाय जी का स्वागत किया उसके बाद विधायक सुरेश बैठा जी, संरक्षक कुमार राजा एवं संयोजक दीपक लाल को अंग वस्त्र एवं पहाड़ी बाबा का प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। सभी लोग हर सम्भव महासमिति के साथ हैं और इस वर्ष शिव वारात भव्य और विशाल हो जो पूरे शहर के मन मोह ले इसके लेकर चर्चा किया।

मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए छह छात्रोपयोगी वेब पोर्टल्स का किया अनावरण



बिभा संवाददाता

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत छात्रोपयोगी वेब पोर्टल्स का अनावरण तथा रांची विज्ञान केंद्र, रांची के नव प्रवर्तन केंद्र का शुभारंभ समारोह एवं झारखंड अनुसंधान तथा नवाचार नीति-2025 हेतु आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विकसित 6 पोर्टल्स का अनावरण एवं रांची विज्ञान केंद्र, रांची अस्थित नव प्रवर्तन केंद्र (इनोवेशन हब) का उद्घाटन किया।

विभिन्न पोर्टल्स के अनावरण का मुख्य उद्देश्य

वेतन निर्धारण पोर्टल : विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षक कर्मियों के वेतन सत्यापन को सरल बनाने, त्रुटियों को कम करने एवं दक्षता में सुधार करने हेतु वेतन निर्धारण पोर्टल विकसित किया गया है।
लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल : ऑनलाइन मॉड में शिक्षण और प्रशिक्षण सेवाओं का प्रबंधन करेगा एवं संस्थानों में चल रहे शैक्षणिक कार्यक्रमों, प्रशिक्षणों या शिक्षण और विकास कार्यक्रमों के प्रशासन, दस्तावेजीकरण आदि के प्रबंधन करने में मदद करेगा।
निजी विश्वविद्यालय प्रबंधन पोर्टल : निजी विश्वविद्यालय पोर्टल राज्य में नए निजी विश्वविद्यालयों के स्थापना एवं प्रबंधन की प्रक्रिया को सरल बनाएगा।
मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना पोर्टल : उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, उच्च शिक्षण संस्थानों स्तर पर शोध को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू हेतु

यह पोर्टल विकसित किया गया है। इससे विद्यार्थियों को फेलोशिप हेतु आवेदन एवं इसका लाभप्राप्त करने में आसानी होगी।
अप्रेंटिस प्रबंधन पोर्टल : राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों तथा विभागान्तर्गत अन्य संस्थानों में अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं का चयन करते हुए उन्हें प्रशिक्षित किया जाना है। उक्त प्रशिक्षुओं के चयन प्रक्रिया को सरल एवं सुलभ करने हेतु अप्रेंटिस प्रबंधन पोर्टल विकसित किया गया है।
वित्त रहित कॉलेज अनुदान पोर्टल : राज्य में वित्त रहित स्थायी संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने की मौजूदा प्रक्रिया में न केवल समय लग रहा है, बल्कि निरीक्षण और सत्यापन के कई स्तर भी हैं। इस पोर्टल के विकसित होने से महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने की प्रक्रिया सरल होगी और समय भी कम लगेगा।

शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल मोड में ले जाने का प्रयास : सुदिव्य कुमार

रांची : उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा की पहुँच को सरल बनाने हेतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उद्देश्य को सार्थक बनाने की ओर बढ़ाए गए इस ठोस कदम के लिए मैं विभाग के पदाधिकारियों का स्वागत करता हूँ, यहाँ उपस्थित गणमान्य अतिथियों एवं पदाधिकारियों को मैं अपनी ओर से बहुत-बहुत आभार एवं शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राज्य के बच्चों को दक्ष बनाना सरकार की प्राथमिकता है। दक्षता के क्षेत्र में झारखण्ड के विद्यार्थियों को आगे रखने के उद्देश्य को पूरा करने के

लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत विभिन्न पोर्टल्स का शुभारंभ होना एक सकारात्मक पहल है। इन महत्वपूर्ण पोर्टल्स की लॉन्चिंग आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करकमलों से हुआ है। इन पोर्टल्स के जरिए राज्य की शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल मोड में ले जाने का प्रयास किया गया है। अब आवेदनों की लंबी परिपटी और धीमा वर्क कल्चर के इतिहास से निकलना है। अब पोर्टल में किसका आवेदन पड़ा है यह सबके समक्ष प्रदर्शित होता रहेगा। आवेदन करने वालों को पता

होगा, उनका आवेदन किसके पास लंबित है और आवेदन प्राप्त करने वाले को भी इसकी जानकारी मिलती रहेगी। मैं स्वयं इसकी निगरानी करूँगा। उन्होंने कहा कि हमलोगों ने नए कदम की शुरुआत की है। मैं मानता हूँ हम लक्ष्य डायरेक्ट, लेकिन फिर संभलेंगे और नया कदम आगे बढ़ाएँगे। मैं विभागीय अधिकारियों से आग्रह करता हूँ कि पोर्टल से किसी को असुविधा न हो, एक क्लिक में उन्हें जानकारी प्राप्त हो। किसी भी तरह के शिकायत का निस्तारण यथा शीघ्र करने का प्रयास सुनिश्चित किया जाए।

कार्यक्रम में ये रहा खास

रांची विश्वविद्यालय, रांची के प्रस्तावित नए भवन का प्रेजेंटेशन :

रांची विश्वविद्यालय का नया भवन कुल ₹० 1100 करोड़ की लागत से रांची जिला के चेड़ी में अवस्थित 87 एकड़ भूमि पर स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में रांची विश्वविद्यालय, रांची के नए परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इस नए परिसर में राज्य के 30,000 छात्र-छात्राओं को विश्वस्तरीय सुविधा के साथ शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा।

झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी, 2025 का उद्देश्य :

राज्य में छात्रों के बीच अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा के उद्देश्य से झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी, 2025 तैयार की जा रही है। यह नीति उच्च शिक्षा में अनुसंधान के एकीकरण पर जोर देती है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। यह नीति स्टार्टअप के लिए सीड फंडिंग और अनुसंधान परियोजनाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों के लिए अनुदान प्रदान करती है। ₹० 1,280 करोड़ के बजट के साथ यह नीति झारखंड छात्र अनुसंधान एवं नवाचार निधि के तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को संस्थान अनुसंधान और इनोवेशन सेल की स्थापना के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। झारखंड को अनुसंधान-आधारित आर्थिक और तकनीकी विकास का एक प्रमुख केंद्र बनाने में यह नीति सहायक होगी।

इसके निर्माण से रांची में वैज्ञानिक प्रदर्शन के साथ-साथ वैज्ञानिक पर्यटन को बढ़ावा मंजूर/जन का साधन भी मिलेगा। पर्यटकों के दर्शन हेतु उपलब्ध होगा।

केशव महतो कमलेश ने नई दिल्ली में झारखंड के नवमनोनीत प्रभारी के राजू से की मुलाकात

बिभा संवाददाता

रांची : झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आज नई दिल्ली में झारखंड के नवमनोनीत प्रभारी श्री के राजू से मुलाकात की।



इस अवसर पर उनके साथ मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र सिंह प्रदेश मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुजनी केदार पासवान एवं रियाज अंसारी भी थे। श्री कमलेश ने प्रभारी श्री के राजू को संगठन द्वारा पिछले 5 महीने के दौरान चलाए गए कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। इस क्रम में उन्होंने विभिन्न जिलों में चलाए गए एजय बापू जय भीम जय सौधानर कार्यक्रम के संदर्भ में चलाए गए विभिन्न चरणों के तहत आयोजित किए गए कार्यक्रम की पूर्ण जानकारी दी। और नवमनोनीत प्रभारी के राजू से मुलाकात की।

वारे में भी चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि जनता दरबार से जन समस्याओं को समझने और उसे दूर करने के लिए जा रहे प्रयासों का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने बताया कि झारखंड में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पेश किये जाने वाले बजट के संदर्भ में आम लोगों तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं विधायकों मंत्रियों से राय लेकर उनकी राय से मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया गया है तथा मुख्यमंत्री ने इस पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है। अन्य समस्याओं के समाधान के लिए कांग्रेस कोटे के मंत्रियों द्वारा किए गए कार्यों की भी पूरी जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस और महागठबंधन के घोषणा पत्र के अनुरूप कार्य करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है इसका परिणाम जल्द ही देखने को मिलेगा।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की समीक्षा बैठक आयोजित राजभाषा हिंदी में कार्य करना व करवाना है तो हमें योजना बनानी पड़ेगी : मुख्य आयकर आयुक्त

बिभा संवाददाता

रांची: मुख्य आयकर आयुक्त, शांतनु धमीजा की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति रांची की छह महीने पर होने वाली समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक इस वित्तीय वर्ष की द्वितीय एवं नराकास की 28वीं बैठक थी।



रांची स्थित नराकास समिति के सदस्य कार्यालयों में से लगभग 130 सदस्य इस बैठक में शामिल हुए जिसमें 45 कार्यालयों के कार्यालय/विभागाध्यक्ष भी शामिल हुए। बैठक का संचालन करते हुए समिति के सचिव डॉ० सुर्यकांत सामल ने अध्यक्ष के साथ-साथ यहाँ उपस्थित सभी विभागाध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों का स्वागत किया। स्वागत भाषण उपरांत बैठक में सम्मिलित सभी विभागों के प्रतिनिधियों ने अपना परिचय दिया। सचिव ने अध्यक्ष के साथ, नराकास

बैठक की महत्ता एवं सदस्य कार्यालयों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में समिति के अध्यक्ष शांतनु धमीजा ने कहा कि ऐसी स्थिति आज नहीं रह गई है जहाँ राजभाषा हिन्दी में काम करना कठिन हो। केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में सरकारी काम में हिन्दी का अधिक-से-अधिक प्रयोग करने की भारतीय संविधान के अनुसार व्यवस्था है। उन्होंने राजभाषा नीतियों, नियमों एवं आदेशों को लागू करने के लिए बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों से आग्रह किया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि यदि अधिक से अधिक राजभाषा हिन्दी में कार्य करना व तकनीकी अंधकार को दूर करने में हमें इस प्रकार से योजना बनानी पड़ेगी कि लोग हमारे पास आएँ और कहें कि मैं हिन्दी में कार्य करना चाहता हूँ।

वर्ष 2023-24 के लिए नराकास के सदस्य कार्यालयों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं में से सर्वश्रेष्ठ प्रथम तीन पत्रिकाओं को अध्यक्ष के कर कमलों से स्मृति चिह्न प्रदान किया गया। कृषि प्रणाली का पहाड़ी एवं पठारी अनुसंधान केंद्र के तकनीकी अधिकारी (राजभाषा), अणिमा प्रभा ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन किया।

सीसीएल के निदेशक हर्ष नाथ मिश्रा टॉप एचआर इनोवेटर पुरस्कार से सम्मानित

रांची : मुंबई में आयोजित वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक हर्ष नाथ मिश्रा को मानव संसाधन प्रबंधन में उत्कृष्ट नवाचार और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए टॉप एचआर इनोवेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान उनके सतत प्रयासों, नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता और संगठन को उत्कृष्टता की दिशा में अग्रसर करने की उनकी प्रभावशाली भूमिका को रेखांकित करता है।



श्री मिश्रा के नेतृत्व में, सीसीएल ने एचआर एवं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली पहल की हैं, जो न केवल संगठन के भीतर एक समावेशी और सशक्त कार्य संस्कृति विकसित कर रही हैं, बल्कि व्यापक सामाजिक प्रभाव भी उत्पन्न कर रही हैं। श्री मिश्रा के मार्गदर्शन में सीसीएल ने मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में अनेक प्रतिशोधनीय नितियों को लागू किया है, जिनमें कर्मचारी सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास, कौशल संवर्धन एवं कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही, सीएसआर के अंतर्गत सीसीएल द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिससे समाज के वंचित वर्गों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है। उनके नेतृत्व में सीसीएल ने एचआर प्रबंधन में नवीनतम प्रथाओं को अपनाने हेतु उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित किए हैं। श्री हर्ष नाथ मिश्रा की यह उपलब्धि संगठन के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, नेतृत्व कौशल और अभिनव सोच का परिचायक है। उनकी कार्यशैली ने सीसीएल को मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान की है और सतत विकास की ओर अग्रसर किया है।

संक्षिप्त खबरें

जया सिंह ने अपने पूरे परिवार के साथ लगाई आस्था की डुबकी



हजारीबाग(बिभा) : प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में, लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम तट पर एकत्रित हो रहे हैं इसी कड़ी में जया सिंह ने अपने पूरे परिवार के साथ संगम में स्नान डुबकी लगाई। मना जाता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया सिंह ने भी इसी श्रद्धा के साथ अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर इस धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न किया। धार्मिक आयोजनों में जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ भाग लेते हैं, तो न केवल उनका आध्यात्मिक विकास होता है, बल्कि आपसी प्रेम और एकता भी मजबूत होती है। परिवार के सदस्यों ने पूजा-पाठ, मंत्रोच्चारण और दान-पुण्य जैसे कार्य किए, जिससे उनका अनुभव और भी पवित्र और संतोषजनक बना होगा। जया सिंह और उनके परिवार का यह कदम समाज में आस्था और धार्मिकता को प्रोत्साहित करने वाला है। जब लोग देखते हैं कि परिवारिक स्तर पर इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं, तो वे भी प्रेरित होते हैं और संस्कृति तथा परंपराओं को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। इन्हें आस्था की डुबकी केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धिकरण और मानसिक शांति का प्रतीक भी है। जया सिंह और उनके परिवार ने इस पवित्र क्रिया को अपनाकर न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। जया सिंह के साथ उनके पति यतीश कुमार, बच्चों में दर्श, रौशनी और अद्विका शामिल रही।

योगेन्द्र प्रसाद से मिले जेएलकेएम नेता देवेन्द्र नाथ महतो सौपा मांग पत्र

रांची(बिभा) : खातियानधारी झारखंडी शराब कारोबार को ही लाईसेंस देने, संपूर्ण झारखंड में एक व्यक्ति/ऐजेंसी/ कंपनी को एक ही लाईसेंस देने तथा मॉडल शॉप, डिपार्टमेंटल स्टोर, मॉल में शराब बिक्री बंद करने का मांग। लंबे समय बाद झारखण्ड सरकार उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग शराब का डुकान निजी हाथों देने जा रही है जिसको लेकर झारखंड उत्पाद एवं मद्य निषेध नियमावली - 2025 नई नियम बनाई जा रहा है जिसका आपत्ति चारों तरफ से हो रही है। झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के वरिष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ महतो विभागीय मंत्री योगेन्द्र प्रसाद जी से मुलाकात कर मांग पत्र सौपा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि जेएलकेएम रांची नशासुक्त झारखंड के पक्षधर है, लेकिन झारखंड सरकार नई उत्पाद एवं मद्य निषेध नियमावली - 2025 लागू करने की तैयारी में है, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा झपट तैयार की गई नई नियमावली - 2025 के तहत राज्य सरकार के स्वामित्व वाले कंपनी (खड्डउड) झारखंड राज्य विवरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी केवल शराब का शौक कारोबार करेगी तथा राज्य में शराब का खुदरा कारोबार शराब व्यापारियों के माध्यम से करने का प्रावधान किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा संचालित लगभग 1453 खुदरा डुकान में कुछ ही गिने - चुने गैर झारखंडी बाहरी लोग एकाधिकार जमाए हुए हैं।

सांसद हुल्लू महतो ने धनबाद में एयरपोर्ट के लिए जमीन जल्द उपलब्ध कराने को लेकर उपायुक्त से की मुलाकात



धनबाद(बिभा) : धनबाद के सांसद हुल्लू महतो के नेतृत्व में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल धनबाद के उपायुक्त महोदय से मिल कर सिंदरी के डोमगढ क्षेत्र में एफ सी आई एल के तुगलकी फरमान से अवगत कराया। माननीय सांसद महोदय ने कहा कि सिंदरी में जब ओबी डम्प के लिए एफ सी आई एल के पास अन्य खाली जमीन उपलब्ध है तो आवासीय क्षेत्र को डिस्टर्ब करने की क्या आवश्यकता है, एफ सी आई एल प्रबंधन बेवजह विधि व्यवस्था बिगाड़ने पर लगा है एवं पीपी कोर्ट के द्वारा लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है जिससे लोगों में भय का माहौल है। माननीय सांसद महोदय ने उपायुक्त महोदय से कहा कि मैं कल सिंदरी गया था और हजारों लोगों ज्यदा तर महिलाएं में जो आक्रोश दिखा वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं दिल्ली में रक्षाधन एवं उर्वरक मंत्रालय में भी इन बातों को रखूंगा आप अपनी तरफ से भी उचित कार्रवाई करें और जब डंप के लिए अन्य जगह उपस्थित है तो आवासीय कॉलोनी को डिस्टर्ब न किया जाए इस स्थिति में यदि कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी एफ सी आई प्रबंधन की होगी। सारी बातों को सुनने के बाद उपायुक्त महोदय ने कहा कि यदि एफ सी आई के पास वैकल्पिक जमीन है तो उसे आवासीय क्षेत्र को डंप के लिए सेल कंपनी को देना उचित नहीं है। जरूरत पड़ी तो मैं आर आर नीति जो एफ सी आई और सेल बनी है उसमें संशोधन करवाने का प्रयास करूंगा। महोदय ने ये पूछा कि कितने ऐसे आवास है उनको बताया गया करीब 1200 से ऊपर आवास है। उपायुक्त महोदय ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि मैं बहुत जल्द इस विषय पर एफ सी आई प्रबंधन से बात कर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। सांसद हुल्लू महतो ने उपायुक्त महोदय से धनबाद में एयरपोर्ट को लेकर जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया जिस पर उपायुक्त महोदय ने त्वरित अंचल अधिकारी की जमीन की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने को कहा प्रतिनिधिमंडल में भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला ग्रामीण के जिला अध्यक्ष घनश्याम श्रोवर, नितिन भट्ट, सिंदरी नगर अध्यक्ष अरविंद पाठक भाजपा के वरिष्ठ नेता दीपक कुमार दीपू, दिनेश सिंह, मणि भूषण सिंह, राजीव सिंह मुन्ना, विदेशी सिंह, धीरज सिंह, आरके सुमन, संजु सिंह अनिल सिंह, प्रकाश श्रीवास्तव, राघव तिवारी सुनील शर्मा थे।

जलापूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में अभियान मोड में कार्य करेगा जिला प्रशासन : उपायुक्त

बिभा संवाददाता

रामगढ़: झारखंड शिक्षा परियोजना, रामगढ़ द्वारा मंगलवार को उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार की अध्यक्षता में टाउन हॉल भवन रामगढ़ में जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम उपायुक्त, जिला परिषद अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त, प्रभारी पदाधिकारी गोपनीय शाखा, नजारत उप समाहर्ता, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा सहित अन्य का सम्मेलन में पौधा देकर स्वागत किया गया जिसके उपरांत सभी ने



दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से सम्मेलन का शुभारंभ किया। मुखिया सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में उपायुक्त चंदन कुमार ने

सभी मुखियाओं एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से नियमित रूप से उनके क्षेत्र में स्थित विद्यालयों का निरीक्षण करने, विद्यालयों में चल रहे

प्रशासन रामगढ़ द्वारा बच्चों को 24. 7 शिक्षा संबंधित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर शुरू की गई योजना की विस्तृत जानकारी दी वही उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बच्चियों को जूटो कराटे का प्रशिक्षण दिए जाने पर भी जिला प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है। आगामी गर्मी के मौसम के मद्देनजर सम्मेलन के दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा इस वर्ष गर्मी के दौरान ग्रामीण सहित अन्य क्षेत्रों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अभियान मोड में कार्य किया जा रहा

है जिसके तहत प्रत्येक पंचायत में कम से कम तीन वैसी जलापूर्ति योजनाएं जो कि वर्तमान में किसी कारणवश खराब हैं उन्हें चिन्हित कर उनकी मरम्मत कराई जाएगी मौके पर उपायुक्त ने सभी जनप्रतिनिधियों से इस पर विशेष ध्यान देने एवं अपने-अपने क्षेत्र में कार्यों का अनुश्रवण करने की अपील की। उपायुक्त ने जिला प्रशासन द्वारा मरम्मत कराए जाने के उपरांत जलापूर्ति योजना के रखरखाव एवं नियमित रूप से जलापूर्ति योजनाओं का कार्य करने को लेकर भी सभी को महत्वपूर्ण जानकारियां दी।

पैगोडा चौक और होली क्रॉस मार्ग, अब शहीद करमजीत सिंह के नाम से जाना जाएगा

प्रमोद खण्डेलवाल

हजारीबाग : झारखंड के वीर सपूत कैप्टन करमजीत सिंह बक्शी (उर्फ पुनीत) ने 11 फरवरी 2025 को जम्मू-कश्मीर के अखनूर सेक्टर में मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके शहीद होने की खबर से पूरा हजारीबाग शोक में डूब गया, लेकिन साथ ही, हर नागरिक ने उनके अदम्य साहस और बलिदान पर गर्व भी महसूस किया। उनका पार्थिव शरीर 12 फरवरी को रांची पहुंचा, और 13 फरवरी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ खिरगांव मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। शहरवासियों, विशेष रूप से सिखा सुमदाय और स्थानीय नागरिकों ने मांग की इस वीर सपूत की स्मृति को चिरस्थायी बनाया जाए। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए सदर विधायक ने एक ऐतिहासिक घोषणा की, जिसके तहत पैगोडा चौक का नाम अब



शहीद करमजीत सिंह चौक होगा वहीं होली क्रॉस रोड अब शहीद करमजीत सिंह मार्ग के नाम से जाना जाएगा।

शहीद की स्मृति को अमर बनाने का संकल्प

यह नामकरण केवल औपचारिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह शहर के नागरिकों की ओर से एक सशक्त संदेश है कि हम अपने वीरों को कभी नहीं भूलेंगे। इसके साथ ही,

नागरिकों ने मांग की इस स्थान पर कैप्टन करमजीत सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनके बलिदान से प्रेरणा ले सकें। इस निर्णय पर शहरवासियों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रही, लेकिन अंततः सभी ने एकमत होकर शहीद के सम्मान में इस बदलाव का समर्थन किया। सभी नागरिकों ने इस अवसर पर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि यह पहल युवाओं में

राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करेगी।

श्रद्धांजलि और प्रेरणा का प्रतीक

यह नामकरण केवल एक परिवर्तन नहीं, बल्कि बलिदान और सम्मान का प्रतीक है। शहीद करमजीत सिंह चौक और मार्ग आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाते रहेंगे कि देश की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता।

मिशन हॉस्पिटल में आयोजित दो दिवसीय निशुल्क 'जननी स्वास्थ्य मेला' संपन्न

बिभा संवाददाता

हजारीबाग: हजारीबाग मिशन रोड रविन्द्र पथ अवस्थित श्रीनिवास सर्वमंगलम सोसाइटी के सहयोग द्वारा संचालित संत कोलम्बस मिशन हॉस्पिटल में आयोजित महिलाओं के विशेष निशुल्क 'जननी स्वास्थ्य मेला' दिन मंगलवार को ऐतिहासिक रूप में संपन्न हुआ। जननी स्वास्थ्य मेला में निशुल्क चिकित्सा परामर्श, मुफ्त दवा, बी.पी जांच, अल्ट्रासाउंड, कैसर स्क्रीनिंग, नेत्र जांच, एक समय का भोजन, दंत जांच एवं शुगर व हीमोग्लोबिन का जांच एवं इलाज मुफ्त किया गया। स्वास्थ्य मेला के माध्यम से डेयर ट्रांसप्लॉट एवं अन्य जांच में भारी छूट दिया गया। जिसमें 2168 महिलाएं सहित कई पुरुषों ने स्वास्थ्य मेला लाभ उठाकर अपना जांच एवं उपचार



करवाया। मुफ्त उपचार करवाकर उत्तम स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त किया। स्वास्थ्य मेला के दौरान एक नवजात शिशु ने भी नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से जन्म लिया। अस्पताल परिवार की ओर से मां एवं नवजात शिशु को कुंके भेटकर स्वागत व अभिनंदन किया गया। स्वास्थ्य मेला में चिकित्सक डॉ जे के आर्य, डॉ एएन सिंह, डॉ पूजा बैरवा, डॉ फेरम कटरा, डॉ रणजीत, डॉ रिकू

यादव, डॉ मिताली सोहन, डॉ प्रिंस कुमार एवं डॉ मधु झा सहित कई स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना सरहानीय योगदान दिया। मौके पर संत कोलम्बस मिशन हॉस्पिटल के संचालक डॉ प्रवीण श्रीनिवास ने कहा कि जननी स्वास्थ्य मेला का उद्देश्य सार्थक हुआ। बड़ी संख्या में सुदूरवर्ती ग्रामीण एवं शहर की महिलाएं व कई पुरुषों ने अपना जांच एवं उपचार करवाया। संत कोलम्बस मिशन हॉस्पिटल आगे भी समाजिक सरोकार से जुड़कर इस प्रकार का निशुल्क शिविर आयोजित कर जरूरतमंदों को उत्तम स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मेला में हमारे चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी एवं ऑफिस कर्मियों ने अपना सरहानीय योगदान देकर शिविर को सफलतापूर्वक संपन्न कर काफी ऐतिहासिक बनाया।

बिभा संवाददाता

हजारीबाग: जीतो हजारीबाग लेडीज विंग ने आज अहम योग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रमुख योग प्रशिक्षिका चेलना जैन ने भाग लिया इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में योग और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना था कार्यक्रम की शुरुआत चेलना जैन द्वारा योग के महत्व और उसके लाभों पर प्रकाश डालने से हुई उन्होंने बताया कि नियमित योग अभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। इसके पश्चात, उन्होंने विभिन्न योग कराए। प्रत्येक आसन के दौरान, चेलना जैन ने उसकी



सही तकनीक, लाभ और सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी योग सत्र के बाद शामिल महिलाओं के लिए एक प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने अपने संदेह और प्रश्नों को साझा किया चेलना जैन ने सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए योग से संबंधित मिथकों को दूर किया और दैनिक जीवन में योग को शामिल करने

के तरीकों पर सुझाव दिए। जीतो हजारीबाग लेडीज विंग की चीफ सेक्रेटरी रजनी जैन ने बताया कि हमारी संस्था लगातार सामाजिक और धार्मिक कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती है। इस तरीके के कार्यक्रम में सदस्यों में काफी उत्साह और समर्थन बढ़ता है। आने वाले दिनों में संस्था द्वारा और भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

झामुमो रांची जिला संयोजक मंडली ने कांटाटोली चौक रांची मे चलाया सदस्यता अभियान

बिभा संवाददाता

रांची : झामुमो रांची जिला संयोजक मंडली के तत्वावधान में आज दिनांक 18 फरवरी 2025 को रांची महानगर अंतर्गत कांटाटोली चौक के समीप, रांची में शिविर लगाकर सदस्यता अभियान चलाया गया। झामुमो के वरिष्ठ नेतृत्व के निर्देशानुसार रांची जिला संयोजक प्रमुख मुस्ताक आलम जी की अध्यक्षता में चलाए गए सदस्यता अभियान में मुख्य रूप से रांची जिला संयोजक मंडली सदस्य पवन जेडीया, अर्चिष्वनी शर्मा, नयनतारा उरांव, एवं अफरोज आलम, जीत गुप्ता, आदिल इमाम, फरीद खान, सोहेल खान, अजीत नायक, आरिज खान, सुजीत कुजूर, आशुतोष वर्मा, अकबर कुरैशी, मो निजाम, उषा उरांव, अशोक लोहार, परवेज आलम, विश्वजीत गोप, मो साजिद, राजेश सिंह, सुजीत उपाध्याय, अवधेश यादव, विजय रविदास, दिलबर सुरीन,



लाडले खान, साहिल यादव, मो परवेज, राकेश, कामरान, मो सन्नी, बाबू, सोनू, बबलू, प्रिंस खान, संयोजक मंडली के सदस्यगणों और जिला व रांची महानगर के वरिष्ठ नेतागणों ने सदस्यता रसीद देकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। मौके पर झामुमो रांची जिला संयोजक प्रमुख मुस्ताक आलम जी ने कहा रांची महानगर के अंतर्गत आज कांटाटोली में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि आजातता है सदस्यता अभियान में पार्टी का 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था। लोगों का

जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं रहीं। पार्टी से जुड़ने वाले सभी नए सदस्यों को जिला संयोजक प्रमुख, संयोजक मंडली के सदस्यगणों और जिला व रांची महानगर के वरिष्ठ नेतागणों ने सदस्यता रसीद देकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। मौके पर झामुमो रांची जिला संयोजक प्रमुख मुस्ताक आलम जी ने कहा रांची महानगर के अंतर्गत आज कांटाटोली में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि आजातता है सदस्यता अभियान में पार्टी का 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था। लोगों का

पार्टी के जुड़ने के उत्साह को देखते हुए उस लक्ष्य को 60 लाख कर दिया गया है। और रांची जिला को जो लक्ष्य मिला है उसमें हमलोग अभी तक 70 प्रतिशत पूरा कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कार्यों से प्रभावित होकर सदस्यता अभियान कार्यक्रम में लग रहे शिविरों में पार्टी से जुड़ने के लिए आप देख रहे हैं लोगों का हजूम उमड़ रहा है। निश्चित झारखण्ड मुक्ति मोर्चा गांवों के साथ साथ अब शहरों में भी पहले से और मजबूत हो रही है।

उप विकास आयुक्त ने जन शिकायत निवारण का किया आयोजन

बिभा संवाददाता

लातेहार: उप विकास आयुक्त के कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण का आयोजन किया गया। जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने अपनी-अपनी समस्याओं को उप विकास आयुक्त के समक्ष रखा। जन शिकायत निवारण के दौरान उप विकास आयुक्त ने वहां उपस्थित सभी लोगों से एकद्वेषक कर उनकी समस्याएँ सुनी एवं अस्वास्थ्य दिशा कि उनके सभी शिकायतों का निष्पादन जल्द कराते हुए, समाधान किया जाएगा। जन शिकायत में प्राप्त आवेदन के आलोक में उप विकास आयुक्त ने समस्या निदान के लिए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। आज के जन शिकायत निवारण में कुल 10 आवेदन प्राप्त हुए जो मुख्य रूप से भूमि विवाद, भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने संबंधित, रोजगार, पेंशन, संबंधी जुड़े आवेदन आये। इस दौरान कुछ

आवेदकों की समस्याओं का निष्पादन आन द स्पॉट किया गया और शेष आवेदकों के समस्याओं का यथाशीघ्र निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। जन शिकायत में सभी शिकायतकर्ता की समस्याएँ को सुनने के पश्चात उप विकास आयुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देशित किया कि सभी आवेदनों का भौतिक सत्यापन करते हुए, समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करें। इस दौरान जनशिकायत प्रभारी पदाधिकारी श्री श्रेयांस भी मौजूद थे। उपायुक्त के निर्देशानुसार आमजन की समस्याओं के समाधान और शिकायत के निष्पादन हेतु जिला, अनुमंडल, प्रखंड स्तरीय के सभी पदाधिकारियों के कार्यालय में प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को जन शिकायत निवारण का आयोजन किया जाता है।

डॉक्टर बनने के लिए क्यों देश छोड़ रहे भारतीय छात्र?



कामकाजी परिस्थितियाँ, प्रोत्साहन और अधिक वेतन प्रदान करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) वंचित क्षेत्रों में एम्स जैसे संस्थान स्थापित करना चाहती है। प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना अति आवश्यक है। ई-संजीवनी टेलीमैडिसिन पहल की वजह से दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार हुआ है, जिसने 14 करोड़ से अधिक परामर्शों को सक्षम किया है। मेडिकल सीटें बढ़ाने, निजी कॉलेज ट्यूशन को नियंत्रित करने और एफएमजी एकीकरण को मजबूत करने की तीन-आयामी रणनीति आवश्यक है। संकाय मानकों और मेडिकल सीट वितरण के सम्बंध में एनएमसी के 2023 के सुधार सकारात्मक कदम हैं। इसके अलावा, ग्रामीण सेवा को प्रोत्साहित करना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी बनाकर भारत की स्वतंत्रता की गारंटी देते हुए गुणवत्ता और पहुँच में सुधार कर सकता है। भारत से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस प्रवास के बारे में मेरी कोई बुरी नहीं है। भारत में, चिकित्सा शिक्षा बेहद महंगी है। प्रवेश की बाधाएँ तकनीकी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से और छात्र डॉक्टर बनने में सक्षम हैं। भारत में और अधिक डॉक्टरों की सख्त जरूरत है, खासकर उन लोगों की जो देश के ग्रामीण इलाकों में काम करने के इच्छुक हैं। स्वास्थ्य सेवा में इन देशों की उपलब्धियों को देखते हुए, मध्य एशिया में चिकित्सा शिक्षा खराब नहीं है। यदि वे भारतीय छात्रों के नामांकन का उपयोग क्षमता उपयोग बढ़ाने और अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए करते हैं, तो वहाँ के कॉलेज अधिक प्रभावी और स्थायी रूप से कार्य करेंगे। अगर इससे भारतीय छात्रों के एक समूह को डॉक्टर बनने में मदद मिलती है तो यह दोनों पक्षों के लिए जीत वाली स्थिति है। असफलता की भी संभावना है। कुछ लोग भारत में काम करने की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। कुछ उच्च-एजेंट या निजी ठेकेदार अधिक छात्रों को आकर्षित करने के प्रयास में कुछ प्रासंगिक जानकारी को रोक सकते हैं। तब आपातकालीन स्थितियाँ हो सकती हैं, जैसे कि चीन में कोविड-19 महामारी या यूक्रेन में युद्ध। इनके परिणामस्वरूप छात्रों के एक समूह को महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत सरकार की नीति आपातकालीन स्थितियों में भी छात्रों की मदद करने में बहुत अच्छी नहीं है। विदेशों में चिकित्सा शिक्षा के सम्बंध में भारत सरकार की एकमात्र बाधावादी भारत में अभ्यास के लिए योग्यता परीक्षा को और अधिक कठोर बनाना है। यह सवाल विवादास्पद है कि ऐसी परीक्षा कितनी कठिन होनी चाहिए। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या भारत में पर्याप्त योग्य चिकित्सा पेशेवर हैं या क्या इसका उद्देश्य लोगों को विदेशों में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने से रोकना है। (यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)



डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत छोड़ने वाले मेडिकल छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है, हर साल 30, 000 से अधिक छात्र विदेश जाते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के आंकड़ों के अनुसार, केवल 16 प्रतिशत विदेशी मेडिकल स्नातक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन स्क्रॉनिंग परीक्षा पास करते हैं। नीट प्रतियोगिता, उच्च ट्यूशन और घरेलू सीटों की कमी के कारण, भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली त्रस्त है, जिसके कारण विदेशी शिक्षा पर निर्भरता बढ़ रही है।

घरेलू मेडिकल संस्थानों में उपलब्ध कुछ सीटों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा और इस तथ्य के कारण कि कुछ देश बहुत कम ट्यूशन फीस देते हैं, भारतीय छात्र अक्सर विदेश में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करना चुनते हैं। इससे उन्हें अधिक किफायती लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। अन्य आकर्षक कारणों में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा पद्धतियों से परिचित होना, निजी कॉलेजों में उच्च ट्यूशन फीस, अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा पद्धतियों से परिचित होना और कुछ देशों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा शामिल हैं। इसलिए, इन छात्रों का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करना और भारत वापस आना है। (भले ही कुछ लोग विदेश में बसना चाहते हों, लेकिन यह प्रवृत्ति भारत में चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों से बहुत अलग नहीं हो सकती है)। इसलिए, विदेशी चिकित्सा-स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने की उनकी क्षमता मुख्य चिंता है। क्या सरकार इसे समाप्त कर देगी और इसकी जगह सभी छात्रों के लिए एक परीक्षा लाएगी, चाहे डिग्री भारत से हो या विदेश से? मुख्य मुद्दा यह है कि क्या भारत में पर्याप्त योग्य चिकित्सा पेशेवर हैं या क्या इसका उद्देश्य लोगों को विदेशों में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने से रोकना है। भारत छोड़ने वाले मेडिकल छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है, हर साल 30, 000 से अधिक छात्र विदेश जाते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के आंकड़ों के अनुसार, केवल 16 प्रतिशत विदेशी मेडिकल स्नातक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन स्क्रॉनिंग परीक्षा पास करते हैं। नीट प्रतियोगिता, उच्च ट्यूशन और घरेलू सीटों की कमी के कारण, भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली त्रस्त है, जिसके कारण विदेशी शिक्षा पर निर्भरता बढ़ रही है। कम ट्यूशन लागत, सुव्यवस्थित प्रवेश प्रक्रिया और मान्यता प्राप्त डिग्री के साथ, कई देश यात्रा के लिए पसंदीदा गंतव्य हैं। इन कारणों के कारण, छात्रों की बढ़ती संख्या भारत के बाहर चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करके अंतर को पाट रही है, जिससे यह गारंटी मिलती है कि वे अभी भी डॉक्टर बनने की अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। आसान आवेदन और प्रवेश प्रक्रिया के कारण भारतीय छात्र अंतरराष्ट्रीय मेडिकल कोर्स को प्राथमिकता देते हैं। छात्र अंग्रेजी या कोई विदेशी भाषा पढ़ सकते हैं। हर साल ट्यूशन पर लगभग 200, 000 से 300, 000 रुपये खर्च होते हैं। कोई कैपिटेशन शुल्क की आवश्यकता नहीं है। कई अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता मिली है। छात्रों को एक बहुसांस्कृतिक सेटिंग से अवगत कराया जाता है जो उनके जीवन के अनुभवों और ज्ञान को व्यापक बनाता है। अच्छी शैक्षिक गुणवत्ता के साथ इनकी डिग्री अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार मान्यता प्राप्त है। घरेलू सीटों के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय मेडिकल छात्र तेजी से देश छोड़ रहे हैं। भारत में छात्र भयंकर प्रतिस्पर्धा के कारण विदेशों में विकल्प

संपादकीय

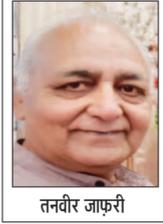
सराहनीय फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर वरिष्ठों के बर्ताव को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को डांट-फटकार को इरादतन किया गया अपमान नहीं माना जा सकता, जिस पर आपराधिक कार्यवाही की जरूरत हो। ऐसे मामलों में व्यक्तियों के विरोध आपराधिक आरोप लगाने की अनुमति देने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पीट ने कहा महज गाली-गलौच, असभ्यता व अशिष्टता भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत आदान किया गया अपमान नहीं है। यह धारा शांति भंग करने के इरादे से जान-बूझकर अपमान करने से संबंधित है, जिसमें दो साल की सजा का प्रावधान है। मामले में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान के कार्यवाहक निदेशक पर सहायक प्रोफेसर को अपमान करने का आरोप था। शिकायतकर्ता के अनुसार निदेशक ने अन्य कर्मचारियों के समक्ष डांट व फटकारा था। यह सच है कि कार्यस्थल से संबंधित अनुशासन और कर्तव्यों के निर्वहन से जुड़ी फटकार, जो व्यक्ति कार्यस्थल पर प्रबंधन करता है, वह अधीनस्थों से अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा व समर्पण से पूरी करने की उम्मीद करेगा। हालांकि स्पष्ट तौर पर देखने में आता है कि अनुशासन के नाम पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों के साथ संतुलित बर्ताव का अभाव नजर आता है। लहजा गलत हो भी तो नीवत बुरी नहीं होनी चाहिए, परंतु इस बारीक अंतर को समझना या समझना पाना भी आसान नहीं है। सेना के सख्त अनुशासन के दरम्यान कई बार ऐसी खबरें आती रहती हैं, जहां नीचे के ओहदे के सैनिक द्वारा अपने अधिकारी की हत्या तक कर दी गई। तब रूप से काम का दबाव, उच्च दर्जे की तामील, पाबंदियाँ और तब तक पर जिम्मेदारियों का निर्वहन अधिकारियों के जेहन पर खालसा दबाव बनाते हैं। वे भी तनावग्रस्त या काम के बोझ के चलते सामान्य बर्ताव करने से चूक सकते हैं। यहां बात सिर्फ उच्चधिकारियों या कनिष्ठों तक ही सीमित नहीं है। कार्य-स्थल पर अभद्र भाषा या गाली-गलौच करने वाले अशिष्ट अधिकारियों के बर्ताव को लेकर भी कर्मचारी धुंख रहते हैं। ज्यों कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न व अभद्र बर्ताव को लेकर कानून बनाए गए हैं। वैसे ही समस्त कर्मचारियों के हित में भी व्यवहारगत संहिता लागू किए जाने की जरूरत है। मानवता कहती है, ओहदे ऊपर-नीचे होने से दोष्य बर्ताव करने का हक किसी को नहीं दिया जा सकता। यह नियम मालिकान व मुलाजिम पर भी लागू होता है।

चितवन-मन

ईश्वर हमेशा भक्तों की सहायता करता है

ईश्वर को हम भले ही न देख पाएँ लेकिन ईश्वर हर क्षण हमें देख रहा होता है। उसकी दृष्टि हमेशा अपने भक्तों एवं सद्ब्यक्तियों पर रहती है। अगर आप गौर करेंगे तो पाएँगे कि जीवन में कभी कठिन समय में ईश्वर स्वयं आकर आपकी सहायता कर चुके हैं। उस कठिन समय में आपके अंदर भक्ति की भावना उमड़ रही होगी और आप ईश्वर को याद कर रहे होंगे। शास्त्रों कहता है कि ईश्वर के लिए संसार का हर जीव उसकी सतान के समान है। जो व्यक्ति उसके बनाये नियमों का पालन करते हुए जीवन यापन करता है ईश्वर उसकी सहायता करेगा। गजराज की कहानी आपने जरूर सुनी या पढ़ी होगी। नदी में गजराज को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। इस कठिन समय में गजराज ने भगवान को पुकारा और भगवान विष्णु प्रकट हो गये। भगवान ने अपने चक्र से मगरमच्छ का सिर काट दिया और गजराज के प्राण की रक्षा की। सूरदास जी के जीवन की भी एक ऐसी ही कथा है। सूरदास जी देख नहीं सकते थे। एक बार गलती से एक गड़दू में गिर गये। गड़दू से निकलने का काफी प्रयास करने पर भी वह बाहर निकलने में असफल रहे। इस स्थिति में सूरदास जी ने गोपाल को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण बालक रूप में पहुँच गये और सूरदास जी को गड़दू से बाहर निकाला। मीरा के प्राण की रक्षा के लिए भगवान ने मीरा को मारने के लिए भेजे गये विष को प्रभावहीन कर दिया। बघेलखण्ड के बांधवगढ़ में रहने वाले सेन नामक नाई की भी भगवान ने सहायता की और बघेलखंड का राजा सेन नाई का भक्त बन गया। यह घटना पाँच छ सौ साल पुरानी है। सेन नाई राजा की सेवा करता था। इसका काम प्रतिदिन राजा की हजामत बनाना और तेल मालिश करके स्नान कराना था।...



तनवीर जाफरी

दिल्ली की 70 सदस्यों की विधान सभा हेतु हुए 2015 के चुनाव में 70 में से 67 सीटें तथा 2019 में दिल्ली की सातवीं विधानसभा चुनाव में 62 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त करने वाली आम आदमी पार्टी पिछले दिनों दिल्ली चुनाव की जीत हार गयी। भारतीय जनता पार्टी को जहाँ पूर्ण बहुमत के साथ जहाँ 48 सीटें हासिल हुईं वहीं आप को केवल 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। आप के लिये सबसे बड़ा झटका यह भी रहा कि सत्ता गंवाने के साथ ही उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल सहित पार्टी के और भी कई दिग्गज नेता चुनाव हार गये। कुछ राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पराजय से पार्टी के अंत की शुरुआत हो चुकी है। यदि ऐसा है तो वास्तव में इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वजह थी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 43.57 प्रतिशत मत प्राप्त होने के बावजूद आप को केवल 22 विधानसभा सीटों पर ही जीत हासिल हुई जबकि भाजपा ने मात्र दो प्रतिशत अधिक यानी 45.56 प्रतिशत मत प्राप्त कर 48 सीटों



प्रियंका सौरभ

राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग ब्यूरो (एनसीआरबी) की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल झूठी शादी की शपथ की आड़ में कई हजार बलात्कार के मामले दर्ज किए जाते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अतुल गौतम मामले में 2025 में दिए गए फैसले से यह सवाल उठता है कि न्यायिक व्याख्याएँ महिलाओं की स्वायत्तता और कानूनी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती हैं? बलात्कार और सेक्स के लिए सहमति देना स्पष्ट रूप से अलग-अलग है। इन स्थितियों में, न्यायालय को सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या शिकायतकर्ता को पीड़िता से शादी करने की वास्तविक इच्छा थी या उसके कोई छिपे हुए उद्देश्य थे और उसने केवल अपनी वासना को शांत करने के लिए इस आशय का झूठा वादा किया था, क्योंकि बाद वाले को धोखा या छल माना जाता है। इसमें अतिरिक्त, झूठा वादा न निभाने और उसे तोड़ देने में अंतर है। अभियुक्त द्वारा अभिवोक्ता को यौन गतिविधि में

केजरीवाल की हठधर्मिता ने दुबोई आप की नैया

पर जीत दर्ज की। नतीजों से साफ है कि भाजपा ने त्रिकोणीय संघर्ष का लाभ उठाकर ही आम आदमी पार्टी से 26 सीटें अधिक हासिल कीं और दिल्ली की सत्ता आप के हाथों से झटक ली। हालांकि हार के बावजूद आम आदमी पार्टी के इस तर्क को भी नकारा नहीं जा सकता कि बावजूद इसके कि बीजेपी के साथ प्रोपेगंडा, सरकार की सारी मशीनरी, मीडिया, धनबल व बाहुबल सब कुछ थे, फिर भी उसे आप से मात्र दो प्रतिशत ही जूझा वोट मिले हैं। सवाल यह है कि 2011 में यू पी ए सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद 26 नवंबर 2012 को देश के अनेक बुद्धिजीवियों द्वारा अरविन्द केजरीवाल के राष्ट्रीय संयोजकत्व में स्थापित की गयी आम आदमी पार्टी जो कि न केवल दिल्ली में सत्ता में थी बल्कि वर्तमान समय में देश के समूद्र राज्य पंजाब में भी सत्ताकूट है वहीं नया नवेली राजनैतिक दल आखिर किन वजहों से और किन परिस्थितियों में इस अजाम तक जा पहुँचा कि आज आप के अंत पर चर्चा छिड़ गयी है? सच पुछिये तो दिल्ली में भाजपा की संभावित फेरह की सुगुणाहट तो दरअसल उसी समय शुरू हो गयी थी जबकि आप ने विगत अक्टूबर 2024 को हरियाणा में हुये विधानसभा चुनाव में इण्डिया गठबंधन घटक का सदस्य होने के बावजूद राज्य की 89 सीटों पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस को हरियाणा की सत्ता में वापसी से रोकेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गौरतलब है कि कांग्रेस हरियाणा में 90 में 7 सीटें आप के लिये छोड़ने को तैयार थी परन्तु केजरीवाल की जिद थी कि कांग्रेस उसे 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने दे। इस बात पर दोनों दलों में समझौता नहीं हो

सका। और आप ने 89 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिये। नतीजतन अहद को राज्य भर में केवल 1.53% वोट प्राप्त हुए। जिन्होंने कांग्रेस को हराने व भाजपा को जिताने में अहम भूमिका निभाई। 2024 में आप द्वारा 10 सीटें तब माँगी जा रही थीं जबकि 2019 में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर टड्डअ से भी काफी कम था। इसी हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद ही दिल्ली में भी इसी तरह के चुनाव परिणाम की उम्मीद की जाने लगी थी। जाहिर है ऐसे विचरसक फैसले लेने के लिये स्वयं अरविन्द केजरीवाल ही जिम्मेदार थे। वैसे भी 2012 में आप अपने गठन के साथ ही उस समय विवादों में आ गयी थी जबकि अन्ना हजारे ने केजरीवाल द्वारा आम आदमी पार्टी के रूप में नया राजनैतिक दल बनाने की कोशिश का विरोध किया था। हालांकि अन्ना हजारे व केजरीवाल दोनों ही नेताओं को लेकर एक बड़े राजनैतिक विश्लेषक वर्ग का यह भी मानना है कि अन्ना आंदोलन या केजरीवाल की तर्ज -ए-सियासत, दरअसल यह सब कांग्रेस के विरोध में तथा भाजपा को फायदा पहुँचाने के लिये रचा गया एक बड़ा राजनैतिक चक्यूह है, अन्यथा क्या कारण है कि जिस जनलोकपाल को लेकर आंदोलन व राजनैतिक दल खड़ा किया गया था उसका जिक्र इन्हीं नेताओं के मुँह से अब क्यों सुनाई नहीं देता। पिछले दस सालों में बड़े से बड़े घोटाले उजागर हुये, उनके विरोध अन्ना हजारे ने आंदोलन क्यों नहीं किया? इसके अलावा आप के गठन के फौन बाद ही जिनसतरह पार्टी के संस्थापक लोगों व अनेक बुद्धिजीवियों द्वारा पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ उसका भी मुख्य कारण केजरीवाल का जिद्दीपन व

उनकी हठधर्मिता ही थी। क्या वजह थी कि आम आदमी पार्टी को सबसे पहले चंदा देने वाले पूर्व कानून मंत्री सुधीर कोर्ट के वरिष्ठ वकील शांति भूषण जिन्होंने पार्टी की स्थापना पर 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया था, 2014 से ही उनका आप से मोहभंग हो गया? शांति भूषण ने उसी समय केजरीवाल को अनुभवहीन, दिल्ली विधानसभा चुनावों में दिकट बंटवारे में गड़बड़ी करने व पार्टी में मनमानी चलाने जैसे अनेक आरोप लगाए थे। इसी तरह केजरीवाल के एक और खास साथी एक्टिविस्ट आशीष खेतान, एक प्रसिद्ध टीवी न्यूज चैनल के मैनेजिंग एडिटर के पद से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले आशुतोष, पार्टी का थिंक टैंक व पार्टी की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले वाले प्रशांत भूषण जैसे साथियों को केजरीवाल संभाल नहीं सके। इसी तरह राजनैतिक विचारक योगेंद्र यादव को जो कि आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाते थे उन्हें भी प्रशांत भूषण के साथ ही पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निकाल दिया गया। समाजशास्त्री आनंद कुमार, पैथोलॉजिस्ट अंजली दमानिया, सामाजिक कार्यकर्ता मयंक गांधी, किरन बेदी, शाजिया इल्मी, विनोद कुमार बिन्नी, कपिल मिश्रा, एमएस धीर सहित और भी कई नेता या तो पार्टी छोड़ गये या फिर निष्क्रिय हो गये। ऐसे सभी नेता केजरीवाल के साथ काम कर पाने में स्वयं को असजज महसूस कर रहे थे। परिणामस्वरूप अनेक साथी नेताओं के मना करने के बावजूद केजरीवाल अपनी जिद में ही दिल्ली में विवादाित शरारत नीति लाये जो कि उनकी राजनैतिक तबाही व बदनामी का कारक साबित हुई।

दुष्कर्म: विवाह के झूठे वादों से बढ़ते मामले

शामिल होने के लिए लुभाने के इरादे के बिना किया गया वादा बलात्कार के रूप में मान्य नहीं होगा। अभिवोक्ता अभियुक्त द्वारा बनाए गए झूठे प्रभाव के बजाय उसके प्रति अपने प्यार और जुनून के आधार पर अभियुक्त के साथ यौन संबंधों के लिए सहमति दे सकती है। वैकल्पिक रूप से, अप्रत्याशित या अनियंत्रित परिस्थितियों के कारण ऐसा करने का इरादा होने के बावजूद अभियुक्त उससे शादी करने में असमर्थ हो सकता है। इन स्थितियों को अलग तरीके से संभालने की जरूरत है। बलात्कार का मामला तभी स्पष्ट होता है जब शिकायतकर्ता का कोई दुर्भाग्यपूर्ण इरादा या गुप्त उद्देश्य हो। अतुल गौतम बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है। यह फैसला अपराण भट बनाम के विपरीत है। 2021 के मध्य प्रदेश राज्य के फैसले में आरोपी और पीड़ित को द्वितीयक आघात से बचने के लिए जमानत पर रहते हुए संवाद करने से मना किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी के लिए, जमानत की आवश्यकताओं को आरोपी और उत्तरजीवी के बीच संचार के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। यह विचार कि विवाह बलात्कार के लिए एक उपाय है न कि अपराध के लिए सजा, ऐसी जमानत आवश्यकताओं द्वारा पुष्ट होता है, जो सामाजिक समझौते को कानून के शासन से आगे रखता है। रामा शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) में जमानत देते समय इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसने प्रतिवादी के खिलाफ अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर कर

दिया। उत्तरजीवी को जमानत प्राप्त करने के लिए आरोपी द्वारा विवाह के लिए मजबूर किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कानूनी व्यवस्था के भीतर रितंत्र दुर्व्यवहार हो सकता है। अभिषेक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024) ने न्याय की गारंटी देने के बजाय, अभियुक्त को विवाह के वादे के बदले में जमानत देकर एक दबावपूर्ण गतिशीलता बनाई। जो उत्तरजीवी को उचित पुनर्वास सहायता प्राप्त करने के बजाय अभियुक्त पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करता है। किशोरों के निजता के अधिकार (2024) में न्यायालय द्वारा उत्तरजीवियों और बच्चों को आवास, शिक्षा और परामर्श प्रदान करने के राज्य के दायित्व पर प्रकाश डाला गया था। जमानत का उद्देश्य सामाजिक कर्तव्यों को लागू करना नहीं है, बल्कि मामला लॉबित रहने तक अस्थायी स्वतंत्रता की गारंटी देना है। न्यायालयों ने पिछले कई निर्णयों में एक पीड़ित के पुनर्वास को विवाह के बराबर माना है, बलात्कार को शारीरिक स्वायत्तता के उल्लंघन के रूप में स्वीकार करने में विफल रहे। न्यायालय महिलाओं की स्वायत्तता को कमजोर करते हुए अपराधियों के साथ विवाह करने के लिए पीड़ितों पर दबाव डालकर कानूनी संरक्षण के तहत दुर्व्यवहार और निरंत्रण को बढ़ावा देते हैं। विवाह को उपाय मानने वाली अदालतें पीड़ित की सहमति की कमी को नजरअंदाज करती हैं, जिसका अर्थ है कि जबरदस्ती को कानूनी रूप से उचित ठहराया जा सकता है। महिलाओं को लगातार आघात और सुरक्षा जोखिमों के बावजूद अक्सर अपने दुर्व्यवहार करने वालों के साथ 'समझौता विवाह' में रहने के लिए मजबूर किया



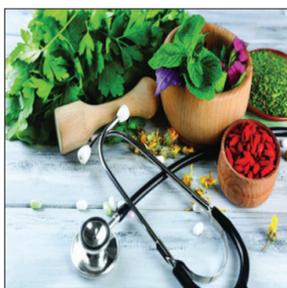
जाता है। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हुए, जो महिलाओं की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा करता है, ऐसे निर्णय महिलाओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध संबंधों में मजबूर करके उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, जबरन विवाह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हैं, जिससे पीड़ितों को न्याय के बजाय अधिक शोषण का सामना करना पड़ता है। ये निर्णय इस धारणा को बनाए रखते हैं कि विवाह यौन हिंसा को हल कर सकता है, इन घटनाओं को गंभीर अपराधों के बजाय नागरिक विवादों में बदल देता है। रिश्ते की जटिलता और धोखाधड़ी के इरादे के बीच अंतर करने के लिए एक अच्छी तरह से कानूनी रणनीति की आवश्यकता होती है। कानूनी सुरक्षा को मजबूत करके और लिंग-संवेदनशील न्यायिक प्रशिक्षण प्रदान करके न्याय किया जा सकता है, जो लैंगिक समानता के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।



नेचुरोपैथी में बनाएं अपना कैरियर

आज के समय में लोगों का लाइफस्टाइल जिस तरह का है, उसके कारण हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से ग्रस्त रहता ही है। लेकिन हर समस्या के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करना उचित नहीं माना जाता। अगर आप भी लोगों का इलाज प्राकृतिक तरीके से करने में विश्वास रखते हैं तो नेचुरोपैथी में अपना भविष्य बना सकते हैं। यह एक ऐसी वैकल्पिक चिकित्सा है, जिसमें प्रकृति के पांच तत्वों की सहायता से व्यक्ति का इलाज किया जाता है। यह इलाज की एक बेहद पुरानी पद्धति है।

इसके अतिरिक्त इसमें डिप्लोमा कोर्स भी अवैलेबल हैं।



स्किल्स

इस क्षेत्र में कैरियर देख रहे व्यक्ति को सामान्य चिकित्सा व मानव शरीर रचना विज्ञान के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक सफल नेचुरोपैथ बनने के लिए आपके भीतर धैर्य, कम्युनिकेशन और लिसनिंग स्किल्स, आत्मविश्वास, मरीज की जरूरतों को समझना, मोटिवेशनल्स स्किल्स व रोगियों के भीतर विश्वास पैदा करने का भी कौशल होना चाहिए।

क्या होता है काम

एक नेचुरोपैथ का मुख्य काम सिर्फ रोगी का इलाज करना ही नहीं होता, बल्कि वह अपने पेशेंट के खानपान और उसके लाइफस्टाइल में भी बदलाव करता है, ताकि व्यक्ति जल्द से जल्द ठीक हो सके। इतना ही नहीं, एक नेचुरोपैथ को मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि वह रोगी की स्थिति को समझकर उसे बेहतर उपचार दे सके।

योग्यता

इस क्षेत्र में कैरियर देख रहे छात्रों का भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान में कम से कम 45 प्रतिशत अंक होने चाहिए। इसके बाद आप बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी और योगिक साइंस कर सकते

एक नेचुरोपैथ यानी प्राकृतिक चिकित्सक का वेतन काफी हद तक उसकी लोकेशन, विशेषज्ञता, योग्यता और अनुभव पर निर्भर करता है। जैसे शुरूआती तौर पर एक नेचुरोपैथ दस हजार से बीस हजार रूपए आसानी से कमा सकता है। एक बार अनुभव प्राप्त करने के बाद आपको आकर्षक वेतन मिल सकता है।

और निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में नियुक्त किए जाते हैं। जैसे लगजरी होटल व हेल्थ रिसॉर्ट में भी नेचुरोपैथ सर्विसेज दी जाती हैं, वहां पर भी जॉब की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आप विभिन्न अखबार, मैगजीन में लिख सकते हैं या फिर खुद का यूट्यूब चैनल चलाकर भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। एक अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक खुद का सेंटर भी खोल सकता है।

आमदनी

एक नेचुरोपैथ यानी प्राकृतिक चिकित्सक का वेतन काफी हद तक उसकी लोकेशन, विशेषज्ञता, योग्यता और अनुभव पर निर्भर करता है। जैसे शुरूआती तौर पर एक नेचुरोपैथ दस हजार से बीस हजार रूपए आसानी से कमा सकता है। एक बार अनुभव प्राप्त करने के बाद आपको आकर्षक वेतन मिल सकता है।

संभावनाएं

एक नेचुरोपैथ वेलेनेस सेंटर, न्यूट्रिशन सेंटर, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेंटर आदि में जॉब तलाश सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप एकेडमिक्स, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज केयर, सोशल वेल्फेयर, मेन्युफैक्चरिंग और नेचुरल प्रॉडक्ट्स कंपनी आदि में भी काम कर सकते हैं। भारत में प्राकृतिक चिकित्सक सरकारी

प्रमुख संस्थान

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली।
- महर्षि पतंजलि इंस्टीट्यूट ऑफ योगा नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च, गुजरात।
- बोर्ड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मेरठ।
- सीएमजे यूनिवर्सिटी, मेघालय।
- प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रांची।
- एसडीएम कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस, कर्नाटक।
- हिमालयन यूनिवर्सिटी, ईटानगर।
- महावीर कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योग, छत्तीसगढ़।

कम्युनिकेशन डिजाइनिंग से दें कैरियर को एक नई उड़ान



बैचलर ऑफ डिजाइन बी.डेस
यह चार वर्षीय पाठ्यक्रम है जो 20 विषयों में उपलब्ध है। 12वीं स्तर के 20 वर्षीय विद्यार्थी इन कोर्स में दाखिला ले सकते हैं।
एनीमेशन फिल्म डिजाइन
कम्युनिकेशन डिजाइन से संबंधित इस कोर्स की अवधि करीबन चार वर्ष की होती है और इसमें महज 15 सीटें ही एनआईडी में उपलब्ध होती हैं। इस कोर्स को करने के बाद छात्र विभिन्न टीवी चैनल में एनिमेटर, करेक्टर डिजाइनर, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, क्रिएटिव डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कंसल्टेंट आदि के रूप में काम कर सकते हैं या फिर

खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं।
सिरामिक एवं ग्लास डिजाइन
सिरामिक एवं ग्लास डिजाइन कला और रचनात्मकता के क्षेत्रों में शिल्प, वास्तु, चिकित्सा, संस्कार, सज्जा उत्पादों आदि शैलियों में कार्यात्मक सम्भावनाएं भी प्रदान करता है। एनआईडी का यह विभाग भारतीय कला और शिल्प से प्रेरणा लेता है और छात्रों को भविष्य में बड़े पैमाने पर उत्पादन और नयी तकनीकों की क्षमता को समझने में मदद करता है। इस कोर्स को करने के बाद छात्र एनजीओ, डिजाइन स्टूडियो, शिल्प उद्योग में भी रोजगार के अवसर ढूँढ सकते हैं

या खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं।
एक्सविशन डिजाइन
कम्युनिकेशन डिजाइन से संबंधित इस कोर्स की अवधि चार वर्ष है। इस कोर्स के दौरान छात्रों में ऐसी समझ का विकास किया जाता है, जिससे खुले और निर्मित स्थानों में संचार के लिए सही परिवेश की स्थापना हो सके। इसके साथ ही ऐसे अनुभवों का निर्माण हो सके जिनके समर्थन से दर्शकों के समक्ष विचारों की व्याख्या हो सके।
फिल्म व वीडियो कम्युनिकेशन
फिल्म व वीडियो कम्युनिकेशन कोर्स के तहत छात्रों को छोटी एजुकेशनल, कल्चरल,

सोशल, एंटरटेनिंग व मार्केट कम्युनिकेशन संबंधी शॉर्ट फिल्म बनाने करने के लिए तैयार किया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद छात्र ऑडियो-विजुअल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। ऐसे छात्रों के लिए एड एजेंसी, फिल्म प्रॉडक्शन हाउस, टीवी चैनल्स व अन्य कई सरकारी क्षेत्रों व एनजीओ के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं।

फर्नीचर डिजाइन
फर्नीचर डिजाइन भी वास्तव में एक कला है और इस कला की पूरी जानकारी एनआईडी के चार वर्षीय फर्नीचर डिजाइन कोर्स से प्राप्त होती है। कोर्स में विभिन्न प्रकार के मैटीरियल, उनके इस्तेमाल और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

ग्राफिक डिजाइन
पिछले कुछ समय से ग्राफिक डिजाइनर की मांग काफी बढ़ी है। ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक लोग ग्राफिक्स का सहारा लेने लगे हैं। इसके जरिए चीजों को आसानी से समझा जा सकता है और यही कारण है कि यह कोर्स छात्रों के बीच खासा पसंद किया जाता है।

जीडीजीपी (ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम इन डिजाइन)
4 वर्ष का यह कोर्स विजयवाड़ा और कुरुक्षेत्र में उपलब्ध है। इसमें छात्रों का 12वीं पास होना आवश्यक है और उम्मीदवार की आयु 20 से अधिक न होनी चाहिए।

प्रॉडक्ट डिजाइन
प्रॉडक्ट डिजाइन उन वस्तुओं की रचना करना है, जो लोगों के लिए फायदेमंद है। वस्तुएं बड़ी व्यवस्था को मुख्य अंश होती हैं। कोर्स के दौरान प्रोजेक्ट्स का मुख्य केंद्र उपयोगकर्ताओं की जरूरत, उत्पाद और आर्थिक प्रभाव के लिए प्रॉडक्ट्स और सर्विसेज पर रहता है।



एक टैटू आर्टिस्ट का काम महज टैटू बनाना ही नहीं होता। वह सबसे पहले अपने क्लाइंट की जरूरत को समझता है और उसके अनुसार अपने क्लाइंट को कुछ बेहतरीन सुझाव देता है। अंत में वह टैटू बनाता है।

पिछले कुछ समय से टैटू बनवाने का क्रेज युवाओं में काफी बढ़ गया है। वैसे तो टैटू पुराने समय से बनाए जाते रहे हैं लेकिन कुछ सालों से इसके स्वरूप में काफी परिवर्तन आया है। वर्तमान समय में सिर्फ आम लोग ही नहीं, बड़े-बड़े स्टार्स भी बांडी पर टैटू बनवाते हैं, फिर चाहे बात दीपिका पादुकोण की हो या प्रियंका चोपड़ा की, हर कोई टैटू बनवा चुकी है। आज के समय में बहुत से ऐसे युवा हैं जो न सिर्फ टैटू बनवाने का क्रेज रखते हैं, बल्कि वह टैटू बनाना भी सीखना चाहते हैं। अगर आपको भी टैटू बनाने का पैशन है तो आप इस क्षेत्र में कैरियर की संभावनाएं देख सकते हैं -

अगर आपको भी है टैटू बनाने का पैशन...



क्या होता है काम
एक टैटू आर्टिस्ट का काम महज टैटू बनाना ही नहीं होता। वह सबसे पहले अपने क्लाइंट की जरूरत को समझता है और उसके अनुसार अपने क्लाइंट को कुछ बेहतरीन सुझाव देता है। अंत में वह टैटू बनाता है। इसके अलावा टैटू बनाने के बाद शुरूआत में स्किन की सही तरह से केयर करनी भी जरूरी होती है, इसलिए एक टैटू मेकर का काम है कि वह अपने क्लाइंट को स्किन के केयर के बारे में भी सारी जानकारी दे ताकि उन्हें बाद में किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े।

स्किल्स

इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत है आपका क्रिएटिव माइंड। आज के समय में पहले की तरह सिंपल टैटू नहीं बनाए जाते। इसलिए एक टैटू मेकर क्लाइंट की जरूरत को समझकर और अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग करके शरीर के विभिन्न



इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप इससे भी अच्छी तरह वाकिफ हों और हर

तरह की सावधानी बरतते हुए ही अपना काम करें।

योग्यता
इस क्षेत्र में कैरियर की संभावनाएं देख रहे छात्रों के लिए कोई मिनिमम योग्यता निर्धारित नहीं है। लेकिन टैटू बनाने में आजकल मशीनों का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए आप किसी टैटू स्टूडियो या संस्थान से शॉर्ट टर्म कोर्स के जरिए टैटू मेकिंग सीख सकते हैं। यह कोर्स एक से दो महीने का होता है।

संभावनाएं
एक टैटू मेकर के लिए काम की कोई कमी नहीं है। टैटू मेकिंग का काम सीखने के बाद आप घर से ही काम की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप बजट अच्छा है तो अलग से टैटू मेकिंग स्टूडियो भी खोला जा सकता है। अगर आप क्लाइंट के घर जाकर काम कर सकते हैं तो ऑनलाइन काम को प्रमोट करना अच्छा रहेगा। इससे आपको कम समय में ही अच्छा काम मिलने लगेगा। इसके अतिरिक्त बड़े-बड़े मॉल्स में भी टैटू मेकिंग का काम शुरू किया जा सकता है।

आमदनी
इस क्षेत्र में कमाई अनुभव और आपके काम के अनुसार बढ़ती है। वैसे कोर्स करने के बाद शुरूआती दौर में एक टैटू मेकर प्रतिमाह 15 से 20 हजार रूपए आसानी से कमा सकता है। लेकिन कुछ सालों के अनुभव के बाद जब आप अपना नाम स्थापित कर लेते हैं तो आपकी आमदनी लाखों में भी हो सकती है।

टेक्सटाइल डिजाइन
टेक्सटाइल डिजाइन के कोर्स के तहत छात्रों के भीतर कपड़ा अथवा टेक्सटाइल की समझ का ज्ञान विकसित किया जाता है। इस कोर्स की अवधि चार वर्ष है।
स्नातकोत्तर डिजाइन (एम.डेस)
किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त छात्र इस कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। 25 वर्ष की अवधि का यह कोर्स अहमदाबाद, बंगलुरु और गांधीनगर कैम्पसों में उपलब्ध है। इन कोर्स में दाखिला लेने वाले आवेदक की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह कोर्स लगभग 19 विषयों में उपलब्ध है, जो इस प्रकार हैं -

- एनीमेशन फिल्म डिजाइन
- अपेरल डिजाइन
- सिरामिक व ग्लास डिजाइन
- डिजाइन फॉर रिटेल एक्सपीरियंस
- डिजिटल गेम डिजाइन
- फिल्म व वीडियो कम्युनिकेशन डिजाइन
- फर्निचर डिजाइन
- ग्राफिक डिजाइन
- इन्फोरमेशन डिजाइन
- इंटरैक्शन डिजाइन
- लाइफस्टाइल पैक्ससेसरी डिजाइन
- न्यू मीडिया डिजाइन
- फोटोग्राफी डिजाइन
- प्रोडक्ट डिजाइन
- स्ट्रेटिजिक डिजाइन प्रबंधन
- टेक्सटाइल डिजाइन
- टॉय एंड गेम डिजाइन
- ट्रांसपोर्टेशन व ऑटोमोबाइल डिजाइन
- यूनिवर्सल डिजाइन

त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की आंकड़ा पहुंचा 55 करोड़ के पार

महाकुंभ नगर। संगमनगरी में 13 जनवरी से आयोजित हो रहा दिव्य-भय धार्मिक, सांस्कृतिक समारोह 'महाकुंभ 2025' में उम्मीद से कहीं अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर इतिहास रच दिया है। यहां अब तक 55 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में स्नानात्न आस्था की पावन डुबकी लगा ली है। 26 फरवरी को शिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व तक यह संख्या 60 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। 26 फरवरी को ही महाकुंभ की समाप्ति भी होनी है। महाकुंभ से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीप जताई थी कि स्नानार्थियों की संख्या का नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। उन्होंने शुरुआत में ही 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई थी। सीएम का यह आंकलन वही 11 फरवरी को ही सच साबित हो गया था। वहीं शुरुआत (14 फरवरी) को यह संख्या 50 करोड़ के ऊपर पहुंच गई और अब इसने 55 करोड़ का नया शिखर छू लिया है। गौरवलेब है कि सर्वाधिक करीब आठ करोड़ श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या पर स्नान किया था, जबकि 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति के अवसर पर अमृत स्नान किया था। एक फरवरी और 30 जनवरी को 2-2 करोड़ के पार और पौष पूर्णिमा पर 1.7 करोड़ श्रद्धालुओं ने पुण्य डुबकी लगाई, इसके अलावा वसंत पंचमी पर 2.57 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई थी। वहीं माघी पूर्णिमा में आस्था की डुबकी लगाई थी। वहीं माघी पूर्णिमा के महत्वपूर्ण स्नान पर्व पर भी दो करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में पावन स्नान किया था।

महात्म सुकेश की याचिका फिर सुप्रीम कोर्ट से खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कथित टमा सुकेश चंद्रशेखर की जेल बदलने की याचिका खारिज कर दी। महात्म दिल्ली की मंडोली जेल और पंजाब की जेल छोड़कर किसी अन्य जेल में भेजने की मांग कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। सुप्रीम कोर्ट की जरिस्ट्रस बेला एम त्रिवेदी और पी बी वराले की बेंच ने कहा कि चंद्रशेखर पहले भी ऐसी कई याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं, जिन्हें खारिज कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास पैसा है, आप उस पैसों से बार-बार याचिका लगावते रहते हैं। बार-बार एक ही याचिका दाखिल करना कानून का दुरुपयोग है। महात्म चंद्रशेखर ने दलील दी कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के कारण उन्हें प्रलाड़ित किया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सरकार बदल गई है, इसलिए उनकी शिकायत का आधार नहीं बचता।

जूनियर छात्र को, सीनियर्स ने गिलास में थूककर पानी दिया और डंडे और बेल्ट से पीटा

-कोट्टायम के सरकारी नर्सिंग कॉलेज में बैंगला का मामला

तिरुअनंतपुरम। केरल के कोट्टायम के सरकारी नर्सिंग कॉलेज में एक जूनियर नर्सिंग छात्र के साथ रैगिंग के बाद एक और मामला सामने आया है। सरकारी कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी की छात्र ने सीनियर्स पर पिटाई करने और बंधक बनाने का आरोप लगाया है। छात्र के मुताबिक घटना 11 फरवरी की है। रैगिंग का आरोप सात सीनियर्स पर लगा है। पीड़ित छात्र ने बताया कि मैं अपने दोस्त के साथ कैम्पस से जा रहा था। तभी सीनियर्स ने हमें रोक लिया। उन्होंने हमारी पिटाई कर दी। इस दौरान मेरा दोस्त वहां से भागने में सफल रहा। दोस्त ने घटना की जानकारी तुरंत प्रिंसिपल को दी। पीड़ित छात्र ने आरोप लगाया कि सीनियर्स ने बांस के डंडे और बेल्ट से पिटाई की। इतना ही नहीं पिटाई के बाद मुझे यूनिट रूम में ले जाया गया। वहां मेरी शर्ट उतार कर मुझे घुटनों के बल बैठा दिया गया। पीने का पानी मांगने पर एक सीनियर ने गिलास में थूककर पानी दिया। सीनियर्स ने रैगिंग के बारे में किसी को भी कुछ न बताने की धमकी दी। छात्र का कहना है कि घटना वाले दिन ही मामले की शिकायत दर्ज करा दी थी। कझाकुट्टम पुलिस ने शिकायत पर 11 फरवरी 2025 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कॉलेज के प्रिंसिपल से अनुरोध किया है कि वे जांच करके हमें रिपोर्ट सौंपे कि क्या संरक्षण में कोई रैगिंग हुई है या नहीं। अधिकारी के मुताबिक प्रिंसिपल ने इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश की। इसमें छात्र की शिकायत सही मिली है। अधिकारी ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर रैगिंग की धारा जोड़ दी गई है। जल्द ही एक रिपोर्ट अदालत को सौंपी जाएगी।

आज जो गालियां दे रहे हैं वहीं कल लालू यादव को भारत रत्न देंगे

-बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी ने जनसभा को किया संबोधित

पटना। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो लोग आज लालू यादव को गालियां दे रहे हैं, वही लोग एक दिन उनका भारत रत्न देगे तेजस्वी ने यह बात बिहार के सीतामढ़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। दरअसल, बीते दिनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर लालू यादव ने रेलवे पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि दुखद घटना घटी है। यह रेलवे की गलती है। रेलवे की लापरवाही से इतने लोगों की मौत हुई है। इस दौरान उन्होंने कुंभ को लेकर भी कहा था कि कुंभ का कहा कोई मतलब है। फालतू है कुंभ उनके इस बयान को लेकर केंद्र और राज्य में सत्ता पक्ष के नेताओं ने उनकी आलोचना की थी। तेजस्वी ने कहा कि जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण को लागू किया था, तो ये लोग उनको भद्दी गालियां देते थे। आज कर्पूरी की ताकत को देखिए जो लोग गाली देते थे, उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। ये है समाजवाद की असली ताकत। उन्होंने कहा कि ये ताकत है कर्पूरी जी की, आज भी कर्पूरी जी प्रसंगिक हैं, जो गाली दिया करते थे, वो भारत रत्न दे रहे हैं। लालू जी को गाली देने वालों से भी हम कहना चाहते हैं कि आज तो लोग लालू जी को गाली दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उनको भी तुम भारत रत्न देने का काम करोगे।

कांग्रेस नेता उदित राज के बिगड़े बोल- कहा मायावती का गला घोटने का समय आ गया

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस नेता उदित राज ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी सुप्रियो मायावती को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उदित राज ने गीता में भगवान श्री कृष्ण के उद्देश का जिक्र करते हुए कहा कि मायावती का गला घोटने का समय आ गया है। दिल्ली के पूर्व सांसद ने कहा उन्हें उनके कृष्ण ने ऐसा करने के लिए कहा है। मायावती ने उदित राज का नाम लिए बिना जवाब दिया है और बयान को गंभीरता से नहीं लेने की बात कही। उदित राज के बोल पर भाजपा ने भी आपत्ति जाहिर की है। उदित राज ने अपने एक्स पर भी अपने बयान को साझा किया है। उन्होंने सोमवार को एक्स पर लिखा, कृष्ण ने कहा था कि न्याय के लिए लड़ो, जरूरत पड़े तो अपने सगे संबंधियों को भी मार दो। बसपा की चीफ सुश्री मायावती जी ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटता है, अब उनका गला घोटने का वक्त आ गया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह बयान दिया।

कांग्रेस नेता ने अपने बयान का वह हिस्सा भी खुद साझा किया है, जिसमें वह कहते हैं, श्रीकृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारे, कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो, मार दो अपने लोगों को ही मार दो, आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसे मार दो। जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटता अब उनका गला घोटने का समय आ गया है।

आकाश आनंद ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम

उदित राज के बयान के बाद बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की तीखी प्रतिक्रिया आई है। आकाश आनंद ने यूपी पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए उदित राज को गिरफ्तार करने की मांग की है। हमारी परमपूज्य आदरणीय

बहन कुं, मायावती जी को गला घोटना की धमकी दे रहा है। मैं यूपी पुलिस से साफ कहना चाहता हूँ की 24 घंटे में इन अपराधियों को गिरफ्तार कर कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें नहीं तो देश का बहुजन युवा चुप बैठने वाला नहीं है, इनको सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है।

गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं: मायावती

मायावती ने उदित राज के बयान पर कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीतेजी और उनके देहांत के बाद भी, करोड़ों शोषित-पीड़ित दलितों/बहुजनों के लिए उनके आत्म-सम्मान और स्वाभिमान के मानवतावादी संघर्ष का हर स्तर पर तिरस्कार करने वाली खासकर कांग्रेस पार्टी कभी भी इनकी सोच-नीतियों पर खरी व विश्वसनीय नहीं हो सकती। मायावती ने कहा, कुछ दलबदल अवसरवादी व स्वार्थी दलित लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो अनर्गल बयानबाजी



आदि करते रहते हैं उनसे भी बहुजन समाज को सावधान रहने व उन्हें गंभीरता से नहीं लेने की जरूरत है क्योंकि वे सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति मूवमेंट से अनभिज्ञ व अपरिचित हैं।

हसीना ने यूनुस को भेजा पैगाम कहा- लौटूंगी और आतंकवादियों की सरकार खत्म कर दूंगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि इशाअल्लाह जल्द ही अपने वतन लौटूंगी और आतंकवादियों की सरकार का खाल्ता करूंगी। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को आतंकवादी करार दिया और कहा कि पुलिसकर्मियों को हत्या का बदला भी लिया जाएगा। बता दें कि बीते साल जून-अगस्त में हुए प्रदर्शनों के दौरान 800 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी मारे गए थे।



पुलिसकर्मियों की मौत का बदला लूंगी। उन्होंने कहा, यूनुस ने अपन अंतरिम सरकार में एक तथाकथित छात्र नेता को शामिल किया है, जो कहते हैं कि पुलिसवालों को मारे बौर आंदोलन नहीं हो सकता। इस अराजकता को हमें खत्म करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 5 अगस्त को वह भीड़ के चंगुल से भागकर आई है, ताकि एक बार फिर बांग्लादेश की जनता की सेवा कर सकें। उन्होंने कहा, मैं आपसे सभी से अनुरोध करती हूँ कि शांत रहें और एकजुट रहें। मैं वापस लौटूंगी और, हमारे शहीदों का बदला लूंगी। मैं पहले की तरह न्याय करूंगी। मेरा वादा है। हिंसा के दौरान कई पुलिसकर्मियों को भी शिराना बनाया गया था। सिराजगंज में एक दर्जन से ज्यादा पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी और उनके शवों को जला दिया गया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हसीना ने हाल ही में जूम लिंक के जरिए 5 विधवाओं और उनके बच्चों से बात की थी। इस वर्युअल मीटिंग को आवामी लीग के अध्यक्ष नजरूल इस्लाम की तरफ से आयोजित किया गया था। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि यूनुस ने बांग्लादेश को आतंकवाद का अड्डा बना दिया है। उन्होंने कहा, यूनुस के पास सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। उन्होंने सभी जांच समितियों को भंग कर दिया है और लोगों को मारने के लिए आतंकवादियों को आजाद कर दिया है। वे बांग्लादेश को तबाह कर रहे हैं। हम आतंकवादियों की इस सरकार को बाहर कर देंगे। इशाअल्लाह। उन्होंने कहा, मैं लौटूंगी और हमारे

आरपीएफ की रिपोर्ट में खुलासा: पलेटफॉर्म बदलने की घोषणा से हुआ दिल्ली में हादसा

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रयागराज जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जूटी भीड़ की भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। हादसे की जांच करने वाली आरपीएफ की टीम ने पाया कि पलेटफॉर्म बदलने की घोषणा न होती हो शायद ये हादसा नहीं होता। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।



रिपोर्ट में कहा गया है कि शनिवार रात 8 बजे पलेटफॉर्म संख्या 12 से शिव गंगा एक्सप्रेस रवाना होने के बाद स्टेशन पर भारी भीड़ जुटने लगी थी। इसके चलते पलेटफॉर्म 12-13, 14-15 और 16 पर जाने वाले रास्ते जाम हो गए। सूचना पाकर एफओबी-2 पर पहुंचे सह सुरक्षा आयुक्त ने स्टेशन निदेशक को स्पेशल गाड़ी को

14 पर मगध एक्सप्रेस और 15 पर उत्तर संपर्क त्रांति एक्सप्रेस खड़ी थीं। पलेटफॉर्म संख्या 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल के यात्री भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। प्रयागराज एक्सप्रेस को मगध एक्सप्रेस छूटने के बाद पलेटफॉर्म -14 पर आना था।

घोषणा सुनकर पलेटफॉर्म संख्या 12-13 और 14-15 से प्रयागराज स्पेशल के यात्री सीढ़ी के रास्ते एफओबी-2 और 3 पर चढ़ने लगे। इसी समय मगध एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस और उत्तर संपर्क त्रांति एक्सप्रेस के यात्री सीढ़ियों से उतर रहे थे। धक्का-मुक्की से कुछ यात्री नीचे गिर पड़े और भगदड़ मच गई। रात 8:48 बजे आरपीएफ के सेक्टर इंचार्ज ने इसकी जानकारी रेलवे अफसरों को दी।

फिर करवट लेगा मौसम! विभाग ने किया 19 से 21 फरवरी तक हाई अलर्ट जारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। नागालैंड और आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 1.5 किमी ऊपर चक्रवातीय पहिंसंचरण सक्रिय है, जिससे मौसम में यह बदलाव देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 19 से 21 फरवरी तक भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने का हाई अलर्ट जारी किया है। वहीं, दिल्ली का मौसम अब बदलने लगा है और तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले कुछ दिनों में

दिन के समय तापमान में इजाफा हुआ है। अब सुबह और रात को ठंडक में भी कमी देखी जा रही है। दोपहर का तापमान बढ़ने लगा है, जिससे हल्की गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 19 और 20 फरवरी को हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में तापमान बढ़ने के पीछे ठंडी हवाओं का कमजोर पड़ना, दिन में धूप बढ़ना और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम

में बदलाव जैसे कारण हैं। इस बदलाव की असर दिल्ली के लोगों को सेहत, जीवनशैली और पर्यावरण पर भी पड़ सकता है। गर्मी बढ़ने के साथ एयर पॉल्यूशन, स्वास्थ्य समस्याएं और फसलों पर असर हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में 19 फरवरी से फिर से मौसम करवट लेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 19 से 23 फरवरी तक प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना है। कई

इलाकों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 19 फरवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी-तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। साथ ही 20 फरवरी को राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में मूसलधार बारिश का ये लो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाओं के चलने और बिजली गिरने से जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है।

लव जिहाद कानून पर महाराष्ट्र सरकार को औवेसी और आजमी ने घेरा

-कहा- इनके पास कोई और काम नहीं, अंकल सरकार बनाने की कोशिश

हैदराबाद (एजेंसी)। महाराष्ट्र सरकार ने जबर्न धर्मतरण और लव जिहाद के कानून को लेकर समिति का गठन किया है। यह इले लेकर सियासत शुरू हो गई है। कमेटी के गठन को लेकर समाजवादी पार्टी नेता और महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी के बाद अब असदुद्दीन औवेसी ने इसपर निशाना साधा है। औवेसी ने सोमवार को इसके खिलाफ एक पोस्टर शेयर किया है।



औवेसी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा-ऐसा लगाता है कि राज्य सरकार के पास अंतरधार्मिक विवाहों की जांच के अलावा कोई और काम नहीं है, क्योंकि उसने अब लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए एक समिति गठित कर दी है।

उन्होंने कहा कि यहां तक कि मोदी सरकार ने भी कहा है कि लव जिहाद की कोई परिभाषा नहीं है और कई जांच एजेंसियों ने साजिश के सिद्धांत को खारिज कर दिया है।

हैदराबाद सांसद औवेसी ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता पहले से ही किसी भी व्यक्ति को अपनी

धार्मिक पहचान छिपाकर शादी का वादा करने पर अपराधी मानता है। जबर्न धर्म परिवर्तन भी अपराध की श्रेणी में आता है। यह केवल अंकल सरकार बनाने की कोशिश है। सरकार इस बात में दखल देती है कि आप किससे शादी करते हैं, क्या खाते हैं, कौन से और कई जांच एजेंसियों ने साजिश के सिद्धांत को खारिज कर दिया है।

ऊपर का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के व्यक्ति से शादी कर सकता है और वह किसी भी धर्म को मान सकता है। लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई हिंदू महिला किसी मुस्लिम से शादी करती है तो वे दबाव झलकर महिला के परिवार का मन बदल देते हैं, जिसके बाद वह कहती है कि उससे जबर्दस्ती शादी करवाई गई। वे बस अबू आजमी ने कहा कि यह देश संविधान और मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं सदियों से हिंदू कानून से चलता है। कानून के तहत 18 साल से

मां की जाति के आधार पर बच्चों को जाति प्रमाण पत्र और ओबीसी सर्टिफिकेट जारी करें

- इसके लिए आपले सरकार पोर्टल पर आवश्यक बदलाव करें

मुंबई (एजेंसी)। बांबंवे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देकर कहा कि असाधारण परिस्थितियों में मां की जाति के आधार पर बच्चों को जाति प्रमाण पत्र और ओबीसी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आपले सरकार पोर्टल पर आवश्यक बदलाव करें। साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से एक समिति भी गठित करने को कह दिया है। ताकि ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के प्रावधानों की संभावना का पता लग सके। बांबंवे हाई कोर्ट ने देवेन्द्र फडणवीस सरकार से कहा कि अपनी मां की सामाजिक स्थिति और जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र चाहने वाले नागरिकों को मां की

सामाजिक स्थिति के दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा मिलानी चाहिए। आपले सरकार राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है, जो नागरिकों के लिए विभिन्न लाभकारी योजनाएं प्रदान करती है और उन्हें शिकायत दर्ज करने में भी सक्षम बनाती है। स्वानुभूति जैन बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले की सुनवाई कर जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस अश्विन डी भोबे की पीठ ने सरकार को सरकारी पोर्टल में संशोधन करने का आदेश दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, खंडपीठ ने 30 वर्षीय महिला स्वानुभूति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर महाराष्ट्र सरकार को पोर्टल पर मां की सामाजिक स्थिति के दस्तावेज अपलोड करने में सक्षम बनाने का आदेश दिया है। स्वानुभूति ने अदालत से राज्य सरकार के अधिकारियों से

प्राधिकारियों को उसकी मां की जाति के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने का आग्रह किया था। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र सरकार को यह निर्देश देने की भी मांग की थी कि आपले पोर्टल पर मुझे अपनी मां की सामाजिक स्थिति के दस्तावेज अपलोड करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि पोर्टल केवल पिता की जाति का दस्तावेज अपलोड करने की अनुमति देता है। हालांकि, हाई कोर्ट ने स्वानुभूति की याचिका खारिज कर कहा कि जैन यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रही कि उसका पालन-पोषण केवल उसकी मां ने किया था या उसकी परिवारिश उसकी मां की जाति की स्थिति से प्रभावित थी। कोर्ट ने कहा कि जैन के पिता, जो एक बैंक अधिकारी हैं, ने उसकी शिक्षा का खर्च उठया

इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, गिरफ्तारी से दी राहत

-कहा- आप लोगों के माता-पिता को बेइज्जत कर रहे हैं, यह गंदे दिमाग की उपज

मुंबई (एजेंसी)। यू-ट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। हालांकि कोर्ट ने रणवीर को गिरफ्तारी से राहत दी है और निर्देश दिया है कि वे जांच में शामिल हों। इसके अलावा संबंधित एपिसोड पर अब कोई और एफआईआर नहीं दर्ज की जाएगी।



वहीं, सुप्रीम कोर्ट में रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि कई राज्यों में मामले दर्ज हैं। उनकी जान को खतरा है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप लोगों के माता-पिता को बेइज्जत कर रहे हैं। यह गंदे दिमाग की उपज है। आपके पास भारी संपत्ति है। दो अलग एफआईआर का आप बचाव कर सकते हैं। हम एफआईआर क्यों क्लब करें। जांच और मुकदमा आपके मुताबिक नहीं चलाया जा सकता। अगर आपको खतरा है, तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और आप शिकायत करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कैसे

व्यवहार करना चाहिए, ये आपको पता है ज्वलनशीलता क्या है आपको पता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सिर्फ दो एफआईआर हैं। एक मुंबई में है और दूसरी गुवाहाटी में है। दोनों एफआईआर भी समान नहीं हैं। दोनों में अलग आरोप हैं। ऐसे में एकसाथ सुनवाई की मांग कैसे की जा सकती है। रणवीर के वकील चंद्रचूड़ ने जुवान काटने के एवज में 5 लाख के इनाम का हवाला दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब आप ऐसी सस्ती पॉपुलैरिटी चाहेंगे तो लोग धमकी तो देंगे ही। आपकी भाषा से अच्छे उसकी भाषा

मां की जाति के आधार पर बच्चों को जाति प्रमाण पत्र और ओबीसी सर्टिफिकेट जारी करें



था और परिवार एक ही घर में साथ रहता था। इसके अतिरिक्त, जैन की मां ने हाल ही में 2022 में अपना

ओबीसी प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, जिसके बाद जैन ने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है।

पैसालो डिजिटल लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए शानदार आय की घोषणा की

मुंबई, एंजेंसी। पैसालो डिजिटल लिमिटेड, एक प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, ने 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए शानदार आय की घोषणा की है। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 12.31 प्रतिशत बढ़कर 47,488 मिलियन रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 42,280 मिलियन रुपये था। कंपनी ने अपने पहले विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड जारी करने में सफलता हासिल की, जिसकी राशि 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 4,230 मिलियन रुपये) है। इस तिमाही में कंपनी ने अपने फ्रैंचाइजी में रिकॉर्ड 1.41 मिलियन नए ग्राहक जोड़े। पहले 9 महीनों में कंपनी ने अपने ग्राहक फ्रैंचाइजी में 4.46 मिलियन ग्राहक जोड़े हैं। कंपनी ने अपने मार्जिन प्रोफाइल को बनाए रखा है, वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में ब्याज आय 25 प्रतिशत बढ़कर 5,773 मिलियन रुपये हो गई, जो वृद्धि 20 वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही 24 में 4,635 मिलियन रुपये थी। कंपनी ने प्रॉफिट बीफोर टैक्स में 7.13 प्रतिशत और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 8.06 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की। इसके अलावा, कंपनी ने बताया कि इसके प्रमोटर समूह ने बाजार लेनदेन के माध्यम से शेयर अधिग्रहित किए हैं। इससे पहले, कंपनी ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा की थी, जिसमें उसने प्रमुख बैंकिंग भागीदारों, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, के साथ मजबूत व्यापार संवाददाता नेटवर्क के माध्यम से दो वर्षों में 3,400 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन शुरू करके 59 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान की। यह ऐतिहासिक उपलब्धि पैसालो की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जो प्रौद्योगिकी और प्रमुख वित्तीय संस्थानों के साथ मजबूत साझेदारी के माध्यम से भारत के अंडर-बैंक आबादी को सहज बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रही है।

अनएकेडमी: जेईई मेन 2025 सेशन 1 के नतीजों ने फिर रचा इतिहास

भोपाल। अनएकेडमी, भारत का प्रमुख एडटेक प्लेटफॉर्म, ने जेईई मेन सेशन-1 2025 के नतीजों के साथ एक बार फिर नए कीर्तिमान स्थापित किया है। अनएकेडमी के 920+ छात्रों ने 99 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर किया है, जो इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा को जोड़ने वाले हाइब्रिड लर्निंग मॉडल की प्रभावशीलता को दर्शाता है। अनएकेडमी के सह-संस्थापक सुमित जैन ने इन शानदार परिणामों पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, हमारे छात्रों ने एक बार फिर अपनी क्षमता और दृढ़ संकल्प को साबित किया है। ये परिणाम हमारे शिक्षकों की प्रतिबद्धता, हमारी अध्ययन सामग्री की गुणवत्ता और हमारे हाइब्रिड लर्निंग मॉडल के प्रभाव को दर्शाते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि यह सिर्फ शुरुआत है और हमारे छात्र जेईई, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में नए रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। शीर्ष स्कोररों में, सौरव ने 100 परसेंटाइल हासिल किया, उनके बाद उज्वल केसरी (99.99 प्रतिशत), समुद्र सरकार (99.92 प्रतिशत), सुजन अग्रवाल (99.98 प्रतिशत), यश कुमार (99.98 प्रतिशत) और कई अन्य प्रतिभाशाली छात्रों ने अपनी मेहनत और लगन का प्रदर्शन किया। उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ, अनएकेडमी लगातार अपने विस्तार को जारी रखते हुए अब भारत के 50 से अधिक शहरों में 75 से अधिक केंद्रों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। यह प्लेटफॉर्म छात्रों को उत्कृष्ट संसाधनों, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और व्यापक शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के अपने मिशन पर दृढ़ बना हुआ है, जिससे वे प्रतियोगी परीक्षाओं में शीर्ष रैंक प्राप्त करने के अपने सपने को साकार कर सकें।

आयकर राहत का मतलब पूंजीगत व्यय से सरकार का ध्यान हटना नहीं: वित्त मंत्री सीतारमण

नई दिल्ली, एंजेंसी। बजट 2025 में दी गई आयकर में भारी छूट का मतलब यह नहीं है कि सरकार ने पूंजीगत व्यय से ध्यान हटाकर खपत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को यह बात कही। वित्त मंत्री की यह प्रतिक्रिया बजट 2025-26 में सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को आयकर के दायरे से बाहर रखने के बाद यह बहस शुरू होने के बाद आई है कि सरकार ने लगातार दो तिमाहियों में जीडीपी के आंकड़ों में धीमी वृद्धि को देखते हुए खपत को बढ़ावा देने पर जोर दिया है।

पूंजीगत व्यय से ध्यान हटाकर खपत पर जोर देने की बात सही नहीं

मुंबई में हितधारकों के साथ बजट के बाद की बातचीत में, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि पूंजीगत व्यय से ध्यान हटाकर खपत पर जोर दिया गया है, सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में पूंजीगत व्यय प्रावधानों में लगातार वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि व्यापक तस्वीर यह है कि कोविड के बाद से सरकार का जोर पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए सार्वजनिक व्यय पर बना हुआ है। इस बार, बजट 2025 में पूंजीगत व्यय पर



खर्च का प्रस्ताव 10.2 प्रतिशत अधिक और लगभग 16 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें पीएसयू पूंजीगत व्यय भी शामिल है। सरकार ने खुद 2025-26 के लिए 11.21 लाख रुपये का पूंजीगत व्यय बजट में रखा है।

2024-25 के संशोधित अनुमानों में 13.18 लाख करोड़ के मुकाबले प्रभावी पूंजीगत व्यय 15.48 लाख करोड़ होने का अनुमान है। प्रभावी पूंजीगत व्यय में मुख्य पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्यों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान शामिल है। हालांकि पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता

पूंजीगत व्यय पर जोर हमेशा से हमारी सरकार की प्राथमिकता

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पूंजीगत व्यय बजट बढ़ाया है और साथ ही कर में कटौती के माध्यम से कुछ रियायतें दी हैं, खासकर व्यक्तिगत आयकर, उन लोगों के लिए जो खर्च करना या बचत करना या निवेश करना चाहते हैं। वित्त ने करदाताओं के बारे में सोचने और उन्हें बड़ी कर राहत देने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस बात पर तुरंत सहमत हो गए कि बजट में 12 लाख रुपये तक की कर राहत का प्रस्ताव होना चाहिए। उन्होंने कहा, आज शायद (यह) ऐसा लग रहा है कि हमने पूंजीगत संपत्ति निर्माण के बजाय उपभोग बढ़ाने पर जोर दिया है, पर पूंजीगत व्यय पर जोर हमेशा से ही हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। सीतारमण ने जोर देकर कहा कि केंद्रीय बजट में आयकर में दी गई छूट और आरबीआई रेपो दर में कटौती से अर्थव्यवस्था में खपत में सुधार को बढ़ावा मिलेगा। 2025-26 के केंद्रीय बजट में आयकर छूट सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे करदाताओं, खासकर मध्यम वर्ग को काफी राहत मिली है।

अनुदान को बजट में राजस्व व्यय के रूप में शामिल किया जाता है, लेकिन वे राज्यों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण पर खर्च होते हैं। वित्त मंत्री ने कहा, मुझे लगता है कि लोगों का यह सोचना कि पूंजीगत व्यय से ध्यान हटाकर उपभोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है, यह सही नहीं है।

बोझ नहीं लगेगा होम लोन का ब्याज, अपनाएं एसआईपी का 15 प्रतिशत फॉर्मूला



नई दिल्ली, एंजेंसी। आरबीआई के रेपो दर घटाने के बाद से कई बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती की है। यह उन लोगों के लिए भी बड़ी राहत है, जो पहली बार मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं। अगर आप भी होम लोन लेकर मकान खरीदना चाहते हैं, तो तय करें कि किस ब्याज दर पर कितने साल के लिए कितना कर्ज लेना है। इस बात

की भी गणना करें कि ऋण अवधि के दौरान आपको अपने कर्ज पर कितना ब्याज चुकाना होगा। गणना करने पर यह समझ में आ जाएगा कि आप जितना कर्ज ले रहे हैं, उससे ज्यादा आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा। ब्याज के रूप में होने वाले इस नुकसान की भरपाई के लिए आप एसआईपी के 15 फीसदी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं।

क्या है 15 फीसदी फॉर्मूला

पूरी कर्ज अवधि के दौरान चुकाए जाने वाले ब्याज का बोझ कम करने में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) का 15 फीसदी का फॉर्मूला काफी मददगार साबित हो सकता है। आप अपने होम लोन पर जितना एसआईपी चुकाते हैं, उसका 15 फीसदी हर महीने एसआईपी में डालना शुरू कर दें। कर्ज अवधि खत्म होते-होते आपके एसआईपी खाते में ब्याज राशि के बराबर या उससे ज्यादा रकम जमा हो जाएगी।

दुल फंड - 39,96,592 रुपये गणना के हिसाब से देखें तो पता चलता है कि होम लोन की पूरी अवधि के दौरान आप जितना ब्याज चुकाते हैं, उससे अधिक रकम आपके एसआईपी खाते में जमा हो गई है।

...तो पूरा कर सकते हैं कर्जमुक्त घर का सपना

अगर आप स्मार्ट निवेशक हैं और एसआईपी में अपना योगदान बढ़ा सकें, तो अपना पूरा घर कर्जमुक्त करा सकते हैं। मान लीजिए, आपने एसआईपी में अपना मासिक योगदान बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिया। सालाना 12 फीसदी के अनुमानित रिटर्न पर यह योगदान 20 साल में बढ़कर 69,94,035 रुपये हो जाएगा। इसमें 53,14,035 रुपये का अनुमानित रिटर्न भी शामिल है। इस तरह, 20 साल बाद आपके एसआईपी खाते में कुल 69,94,035 रुपये जमा हो जाएंगे, जो कुल 63,62,717 रुपये की होम लोन देनदारी से अधिक है। यानी आपका पूरा घर कर्जमुक्त।

एसआरएम इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया इटीग्रेटेड मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम

चेन्नई, एंजेंसी। चेन्नई स्थित एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने हाल ही में एक अभिनव पांच वर्षीय इटीग्रेटेड मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत की है। यह विशेष रूप से अगली पीढ़ी के पब्लिक हेल्थ लीडर्स को तैयार करने के लिए विकसित किया गया है जिससे वे जटिल वैश्विक एवं स्थानीय स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में समर्थ बनेंगे। प्लस टू परीक्षा में न्यूनतम कुल 60 प्रतिशत अंकों के साथ अपनी स्कूल शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों के लिए यह प्रोग्राम खुला है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक सुसंरचित पाठ्यक्रम तैयार किया गया है जो महामारी विज्ञान, जैव सांख्यिकी, स्वास्थ्य प्रणाली एवं नीति, स्वास्थ्य परियोजना प्रबंधन और स्वास्थ्य अनुसंधान को समावेशित करते हुए वैश्विक एवं स्थानीय स्वास्थ्य मुद्दों को एकीकृत करता है। यह अनुसंधान, डेटा एनालिटिक्स और कार्यक्रम मूल्यांकन पर व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान करता है। ग्रेजुएट्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, सीएसआर पहलों, कंसल्टिंग फर्मों, आईटी कंपनियों, हेल्थ इश्योरेंस कंपनियों, फार्मा और बिलिनकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशनों, सरकारी स्वास्थ्य विभागों एवं शिक्षण संस्थानों में अपना विविध करियर बनाने की दिशा में लाभ मिलेगा। उनके पास प्रोग्राम ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर, परियोजना प्रबंधक जैसे भूमिकाएँ अपनाये जा सकेंगी। अतिरिक्त और अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है जो इसे पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल बनने की महत्वकांक्षा रखने वाले छात्रों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाता है।

एक और रेलवे स्टॉक का बुरा हाल, 52 वीक लो पर भाव

नई दिल्ली, एंजेंसी। तीतरगढ़ रेल सिस्टम्स के शेयरों का बुरा हाल है। तिमाही नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में गिरावट का सिलसिला जारी है। आज यानी सोमवार को कंपनी के शेयर 5 प्रतिशत से अधिक लुढ़क गए थे। बता दें, आज से पहले 2 दिन कारोबारी दिन में कंपनी के शेयर 7 प्रतिशत से अधिक टूट गए थे।

आज कंपनी के शेयरों की कीमतों में गिरावट आई है- बीएसई में आज कंपनी के शेयर 803.95 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयर 5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद 762.80 रुपये के स्तर पर आ गया था। यह कंपनी का 52 वीक लो लेवल है। बता दें, 27 जून 2024 को कंपनी का 52 वीक हाई 1896.50 रुपये है। तीतरगढ़ रेल ने बताया है कि दिसंबर तिमाही में कुल नेट प्रॉफिट 62.80 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 16 प्रतिशत की गिरावट आई है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 74.80 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का रेवन्यू सालाना आधार पर 5.5 प्रतिशत की गिरावट के बाद 902.20 करोड़ रुपये रहा है।



2025 के सीजन में चीनी उत्पादन कम होने की उम्मीद

नई दिल्ली, एंजेंसी। भारत के चीनी उद्योग में चालू चीनी सीजन वर्ष 2025 (एसएसएवई25) के लिए उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट देखी जा रही है, जिसमें कुल उत्पादन 27 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) से नीचे गिरने की उम्मीद है। यह पिछले साल के 31.8 एमएमटी के मुकाबले तेज गिरावट है। सेंट्रल ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है। 15 फरवरी, 2025 तक देश में चीनी उत्पादन 19.77 एमएमटी है, यह आंकड़ा पिछले सीजन की इसी अवधि की तुलना में 12 प्रतिशत कम है। उत्पादन में गिरावट मुख्य रूप से इथेनॉल उत्पादन के लिए अधिक चीनी के इस्तेमाल और गन्ने की उपलब्धता में कमी के कारण है।

चीनी के उत्पादन में सबसे ज्यादा कमी महाराष्ट्र में- चीनी उत्पादन के राज्यवार आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां चीनी उत्पादन में सालाना 14 फीसदी की गिरावट आई है। कर्नाटक में 13 फीसदी की गिरावट देखी गई, जबकि उत्तर प्रदेश में 8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। उल्लेखनीय रूप से, पिछले पखवाड़े में कर्नाटक की गन्ना उपलब्धता में साल-दर-साल आधार पर 22 फीसदी की गिरावट आई। महाराष्ट्र में गन्ने की उपलब्धता में सालाना आधार पर 7.8 प्रतिशत कम हुई वहीं यूपी में चालू सीजन के लिए गन्ने की उपलब्धता 1.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अपेक्षाकृत स्थिर रही।

मिलों में गन्ने की आपूर्ति घटने के कारण समय से पहले पेराई बंद

रिपोर्ट के अनुसार घटती गन्ना आपूर्ति ने कई मिलों को उम्मीद से पहले पेराई कार्य बंद करने के लिए मजबूर किया है। 31 जनवरी तक 23 मिलों ने पेराई का काम बंद किया था, जबकि



15 फरवरी तक 51 मिलों ने परिचालन बंद कर दिया। एसएसएवई25 के लिए कुल गन्ना पेराई पिछले सीजन के 228 एमएमटी से 4.5 प्रतिशत कम होकर 218 एमएमटी रह गई। हाल ही में नीतिगत बदलाव करते हुए सरकार ने भारतीय खाद्य निगम चावल के मूल्य वृद्धि को वापस लेते हुए एसे 22.5 रुपये प्रति किलोग्राम तय कर दी है।

इथेनॉल की कीमतों में बदलाव के फैसले से कारोबारी निराश

हालांकि, इथेनॉल मूल्य की कीमतों में बदलाव ने कारोबार से जुड़े लोगों को निराश किया है, क्योंकि केवल सी-हैवी रूट में 3 प्रतिशत की कीमत वृद्धि देखी गई, जो कि बी-हैवी और प्रत्यक्ष इथेनॉल उत्पादन में व्यापक वृद्धि की उम्मीदों के विपरीत है।

उत्पादन में गिरावट के बावजूद चीनी की कीमतें स्थिर और लाभकारी

उद्योग के विशेषज्ञों का सुझाव है कि मिलें सीएच-आधारित इथेनॉल उत्पादन पर जोर दे सकती हैं, जिससे संभावित रूप से चीनी उत्पादन अधिक और इथेनॉल उत्पादन कम हो सकता है। उत्पादन में गिरावट के बावजूद, चीनी की कीमतें स्थिर और लाभकारी बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में चीनी की कीमतें 41,000 रुपये प्रति टन के आसपास हैं, जबकि महाराष्ट्र में कीमतें 37,500 रुपये प्रति टन से ऊपर हैं।

67 के शेयर को खरीदने की मची होड़, लगा 20 प्रतिशत का अपर सर्किट

कंपनी को हो गया 462 प्रतिशत का प्रॉफिट

नई दिल्ली, एंजेंसी। माइक्रो-कैप स्टॉक रिलायबल डेटा सर्विसेज लिमिटेड के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में आज 20 प्रतिशत का अपर सर्किट लग गया और यह 81 रुपये के इंद्रा डे हाई पर पहुंच गया था। इसका पिछला बंद प्राइस 67.50 रुपये है। पांच दिन में यह शेयर 15 प्रतिशत चढ़ गया। पिछले पांच सालों में स्टॉक ने 150 प्रतिशत से अधिक रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे दिसंबर तिमाही के नतीजे हैं।

कंपनी को 462 प्रतिशत का प्रॉफिट - रिलायबल डेटा सर्विसेज लिमिटेड ने रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों में मजबूत तेजी देखी गई है। माइक्रो-कैप कंपनी का दिसंबर साल-दर-साल 462 प्रतिशत प्रॉफिट हुआ है। दिसंबर तिमाही में कंपनी ने 34.29 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया। यह छठे सत्र 24 में 20.52 करोड़ रुपये से 67 प्रतिशत बढ़ोतरी देखी गई। तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 462 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4.11 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह 0.73 करोड़ रुपये था। इसके अलावा तिमाही आधार पर वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट में 1.27 करोड़ रुपये से प्रभावशाली 223 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई।

कंपनी की शेयरहोल्डिंग पैटर्न

दिसंबर 2024 के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार, प्रमोटरों के पास रिलायबल डेटा सर्विसेज लिमिटेड का 71.77 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के पास 0.08 प्रतिशत और खुदरा निवेशकों के पास 28.15 प्रतिशत हिस्सा है। रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि रोहित शर्मा के पास कंपनी में 1.00 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

संक्षिप्त समाचार

सर्बिया में रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 लोगों की मौत

नोवी सैड, एजेंसी। सर्बिया के दूसरे सबसे बड़े शहर नोवी सैड में एक पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 लोगों की मौत के तीन माह बाद भी प्रदर्शन रहे हैं। दोषियों को सख्त सजा दिए जाने व मृतकों के परिजनों के लिए न्याय की मांग करते हुए रिवार को मध्य सर्बियाई शहर कागुजेविक में करीब 15 हजार लोगों ने मोबाइल की प्लेलाइट व टॉर्च जलाकर प्रदर्शन किया।

इस साल जुलाई में ब्रिक्स की मेजबानी करेगा ब्राजील

ब्राज़िलिया, एजेंसी। ब्राजील इस साल जुलाई में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 16 और 7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जनेरियो में होने वाले इस सम्मेलन में भारत के अलावा चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भाग लेंगे। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, ब्राजील 2025 तक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समूह की अध्यक्षता करेगा। इस दौरान वह वैश्विक शासन सुधार और ग्लोबल साउथ (वैश्विक दक्षिण) देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत, ब्राजील, रूस और चीन ने साल 2009 ने ब्रिक की स्थापना की थी। अगले साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका इस संगठन से जुड़ा, जिसके बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। पिछले साल ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ब्रिक्स में शामिल हुए।

नेपाल में एक हफ्ते तक संसद में पेश नहीं होंगे 5 अध्यादेश

काठमांडू, एजेंसी। सरकार ने पांच अध्यादेशों को संसद में पेश किए जाने की योजना अगले हफ्ते तक टाल दी है। नेपाल सरकार ने 18 फरवरी को संसद के दोनों सदनों में अध्यादेश पेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन सांसदों के राजधानी से बाहर होने के कारण अब इसे 23 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया है। सत्ता पक्ष ने भूमि संबंधी अध्यादेश को छोड़कर बाकी पांच अध्यादेशों को संसद से पारित कराने की तैयारी की है। सत्तारूढ़ दल के प्रमुख सचेतकों की रविवार को हुई बैठक में विधेयकों को शीघ्र पारित कराने की रणनीति पर सहमति बनी। सिंह दरबार स्थित सीपीएन-यूएमएल संसदीय दल के कार्यालय में हुई बैठक में अध्यादेशों को पेश करने व उन्हें कार्यसूची में शामिल करने पर भी चर्चा हुई।

सिंगापुर की संसद में झूठ बोलने के दोषी पाए गए भारतवर्षी नेता

सिंगापुर, एजेंसी। सिंगापुर में एक भारतवर्षी सांसद को सिंगापुर की संसद में झूठी गवाही देने का दोषी पाया गया है। भारतवर्षी नेता प्रीतम सिंह ने संसदीय समिति के सामने झूठी गवाही दी, इसके चलते प्रीतम सिंह को संसद सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है और इस साल के आम चुनाव में उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा सकती है। सिंगापुर की अदालत ने प्रीतम सिंह को दोषी माना है। सिंह पर एक अन्य सांसद के मामले में जांच कर रही संसदीय समिति के सामने झूठी गवाही देने का दोषी पाया गया है।

पूर्वी चीन में सख्तान प्रांत से प्राकृतिक गैस की सप्लाई की परियोजना का निर्माण तेज

बीजिंग, एजेंसी। पूर्वी चीन में सख्तान प्रांत से प्राकृतिक गैस की सप्लाई की दूसरी लाइन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की पूर्व खंड परियोजना का निर्माण तेजी से हो रहा है। यह चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना में प्रमुख ऊर्जा बुनियादी संस्थापन परियोजना है। बताया जाता है कि दूसरी लाइन की कुल लंबाई 4,269 कि।मी। है, जो सख्तान, छोंगछिंग, हुपेई, आनह्वेई और च्यांग प्रांत से गुजरती है। पूर्व खंड की लंबाई 2,698 कि।मी। है, जिसमें एक मुख्य लाइन, दो टाई लाइनें और तीन शाखा लाइनें शामिल हैं। पाइपलाइन का डिजाइन दबाव 10 एमपीए है और वार्षिक परिवहन 14 अरब घन मीटर है। अनुमान है कि दूसरी लाइन का निर्माण वर्ष 2027 में पूरा होगा। हाल के वर्षों में चीन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क और गैस भंडारण तथा पीक-शेविंग सुविधा के निर्माण को तेज कर रहा है। अंतःसंबंधन परियोजनाओं में सुविधा आई, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की गई और उच्च गुणवत्ता वाले आर्थिक तथा सामाजिक विकास को सहायता दी गई। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 के अंत तक चीन में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई एक लाख 20 हजार किमी से अधिक है और मुख्य प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क 57 हजार कि.मी. से लंबा है।

हांगकांग में पांडा के जुड़ावां शावकों के लिए नामकरण प्रतियोगिता शुरू

बीजिंग, एजेंसी। हांगकांग में पहले पांडा जुड़ावां शावकों का जन्म 18 अगस्त 2024 को हुआ। छह महीने बाद 16 फरवरी को पांडा जुड़ावां बच्चे हांगकांग के ओशन पार्क में सामने आए। छह महीने के पांडा जुड़ावां शावक पैड़ की शाखाओं और घास पर चढ़ते और खेलते हुए बहुत प्यारे और मनमोहक लगते हैं। बताया जाता है कि जन्म के समय मादा पांडा शिशु का वजन लगभग 122 ग्राम है और नर पांडा शिशु का वजन लगभग 112 ग्राम है। ओशन पार्क की नर्सिंग टीम की देखभाल में अब दोनों का वजन 10 किगोग्राम से अधिक हो गया है। उनकी मां का नाम रिंगिंगिंग है, जो हांगकांग की चीन में वापसी की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर केंद्र सरकार ने हांगकांग को दान किया है।

जर्मनी में एफडी पार्टी सरकार बनाने की दौड़ में आगे

80 साल में पहली बार कट्टरपंथी पार्टी को बढ़त

पिछले चुनाव में सातवें नंबर पर थी, प्रचार में ट्रम्प का मॉडल अपनाया

बर्लिन, एजेंसी। जर्मनी में 23 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। इस बार के चुनाव नतीजे बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। चांसलर ओलाफ शूलज का सत्तारूढ़ एसडीपी गठबंधन प्री-पोल सर्वे में बुरी तरह से पिछड़ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 80 साल में पहली बार कट्टरपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी (एफडी) तेजी से आगे बढ़ी है। अभी एफडी सरकार बनाने की रेस में दूसरे नंबर पर है। जबकि पिछले चुनाव में ये पार्टी 7वें नंबर पर रही थी। एफडी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के चुनाव मॉडल पर प्रचार कर रही है। पार्टी का एजेंडा भी ट्रम्प की लाइन पर है। इस पार्टी ने जर्मनी फर्स्ट का नारा दिया है। एफडी की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लग सकता है कि ये पार्टी हाल में हुए प्रांतीय चुनाव में पांच में से दो प्रांतों में बहुमत हासिल कर चुकी है। संघीय चुनावों में भी इस बार एफडी को रिकॉर्ड वोट मिलने की संभावना है।

एफडी युवाओं में लोकप्रिय, प्रवासियों पर सख्ती

एफडी युवाओं में बेहद लोकप्रिय है। 50 साल से कम उम्र के लगभग 70 प्रतिशत वोट एफडी को वोट देने की बात कह रहे हैं। जर्मनी में कुल लगभग 6 करोड़ वोट हैं। एफडी की नेता एलिस वीडल



भारतीयों पर असर-रिक्ल और स्टूडेंट वीसा में कटौती की आशंका

एफडी की जीत भारतीय हितों पर भारी पड़ सकती है। हाल ही में जर्मनी ने इस साल से भारतीयों को चार गुना अधिक स्किल वीसा जारी करने का ऐलान किया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शूलज ने अक्टूबर में अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा था कि हमारे देश को भारतीय टैलेंट की जरूरत है लेकिन इन चुनावों में कट्टरपंथी एफडी पार्टी को जीत मिलती है तो उसकी जर्मनी फर्स्ट की नीति के तहत जर्मन लोगों को पहले जाँच ऑफ किए जाएंगे। फिलहाल जर्मनी हर साल 20 हजार भारतीयों को स्किल वीसा जारी करता है। शूलज ने इसे बढ़ाकर 80 हजार करने की बात कही थी। अभी जर्मनी में 2 लाख 85 हजार भारतीय रहते हैं। एफडी की सरकार बनने के बाद वर्क वीसा और परमानेंट रेजिडेंसी में भी दिक्कत आ सकती है। जर्मनी में भारतीय छात्रों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। 2021 में जहाँ 25 हजार भारतीय छात्र थे, ये संख्या 2024 में बढ़ कर लगभग दो गुनी हो गई है। जर्मनी में भारतीय छात्र यूरोप में दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर भारतीय छात्र ब्रिटेन में हैं।

प्रवासियों के मुद्दे पर अपने सख्त रुख के लिए जानी जाती हैं। उनका एजेंडा प्रवासियों को वीसा देने में कटौती करना और यूरोपीय यूनियन के साथ संबंधों पर फिर से विचार करना है। यानी एफडी यदि सरकार बनाने में सफल रहती है तो अमेरिका के साथ संबंधों को बढ़ाएगी। एलिस की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सीडीयू के फेडरल मर्ज और एसडीपी के ओलाफ शूलज भी अब प्रवासियों को वीसा में कटौती के मुद्दे को उठा रहे हैं।

पुतिन और मस्क एफडी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क कट्टरपंथी एफडी पार्टी को खुला समर्थन दे रहे हैं। पुतिन का कहना है कि एफडी के सत्ता में आने से रूस के जर्मनी के साथ संबंध और बेहतर होंगे। जबकि मस्क का कहना है कि एफडी की जीत से जर्मनी यूरोप में फिर से शक्तिशाली देश के रूप में उभरेगा। पुतिन-मस्क के समर्थन से एफडी की लोकप्रियता बढ़ रही है। चुनाव में पहली बार भारतवर्षी भी मैदान में हैं। सिद्धार्थ मुद्गल सीएसयू पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुख्य मुद्दा जर्मनी की इकोनॉमी को और बेहतर बनाकर यहां के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

रवांडा समर्थित विद्रोहियों ने कांगो के खनिज समृद्ध पूर्वी क्षेत्र के दूसरे प्रमुख शहर पर कब्जा किया

बुकावु (कांगो), एजेंसी। अफ्रीकी देश कांगो में रवांडा समर्थित विद्रोहियों ने खनिज समृद्ध पूर्वी कांगो के दूसरे प्रमुख शहर पर कब्जा कर लिया है। विद्रोही समूह 'एम23' ने पुष्टि की है कि उसके लड़ाकू बुकावु शहर में हैं और कांगो की सेना के शहर से जाने के बाद उन्होंने यहां की सुरक्षा व्यवस्था संभालने का जिम्मा लिया है। 'द कांगो रिक्टर अलायंस' ने एक बयान में कहा कि उसके लड़ाकू ने 13 लाख की आबादी वाले शहर बुकावु में सुरक्षा चुनौतियों को हल करने और 'बुकावु की जनता की सहायता करने का निर्णय लिया है।' 'द कांगो रिक्टर अलायंस' विद्रोही समूहों का संगठन है जिसमें 'एम23' भी शामिल है। संगठन के प्रवक्ता लॉरेंस कान्यूका ने एक बयान में कहा, 'हमारे बल लोगों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, जिससे पूरी आबादी संतुष्ट है।' ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी बलों ने विद्रोहियों से कोई खास संघर्ष नहीं किया और यहाँ एक भी सैनिक मौजूद नहीं है। शनिवार को हजारों नागरिकों के साथ कई सैनिक भागते हुए देखे गए थे। 'एम23' के एक चरमपंथी बर्नार्ड मंशेरे बयामुंजु ने बुकावु में दक्षिण किबु के गवर्नर कार्यालय के सामने खड़े होकर निवासियों से कहा कि वे 'जंगल' में रह रहे हैं। उसने कहा, 'हम पुराने शासन की अव्यवस्था को दुरुस्त करने जा रहे हैं।

ट्रंप के विदेशी सहायता रोके जाने से मर सकते हैं एड्स के लाखों मरीज, यूएन की चेतावनी

अदिस अबाबा, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही जो शुरूआती फैसले लिए, उनमें अमेरिका द्वारा दुनिया भर में दी जाने वाली विदेशी सहायता पर रोक का फैसला प्रमुख था। अब इस फैसले का असर दिखना शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एड्स प्रोग्राम की निदेशक विनी ब्यानिमा ने चेतावनी दी है कि अमेरिका द्वारा विदेशी सहायता रोके जाने से दुनिया भर में एड्स के लाखों मरीज मर सकते हैं।

अमेरिका, दुनिया में विदेशी सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता

अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र के लिए विदेशी सहायता का दुनिया में सबसे बड़ा प्रदाता है। यह मदद अमेरिका अपने एजेंसी संयुक्त राज्य अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी के द्वारा करता रहा



है। जनवरी में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ट्रंप ने यूएसएआईडी के तहत दी जाने वाली विदेशी सहायता तीन महीने के लिए रोक दी है। इससे मानवीय मदद के कार्यों पर बड़ा असर पड़ेगा है। यूएन-आईडीएस की कार्यकारी निदेशक विनी

ब्यानिमा ने बताया कि अगर विदेशी सहायता के तहत मिलने वाली निधि अगर खत्म हो जाती है, तो लोग मर जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि एड्स से मृत्यु दर दस गुना तक बढ़ सकती है। अफ्रीका में बिगड़ सकते हैं हालात :

फाउंडेशन फॉर एड्स रिसर्च के विश्लेषण के अनुसार, अमेरिकी मदद से दो करोड़ से अधिक एचआईवी रोगियों और 270,000 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद होती है। अगर विदेशी मदद रुकती है तो इससे पांच वर्षों में एड्स से दस गुना अधिक करीब 63 लाख लोगों की मौत हो सकती है। हालांकि अमेरिका ने जीवन रक्षक उपचार की दवाओं में रोक से छूट दी है, लेकिन अफ्रीका में ये सुविधाएं भी बंद हो चुकी हैं। इथियोपियाई राजधानी अदीस अबाबा में अफ्रीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ब्यानिमा ने ये बात कही। साल 1961 में अमेरिका ने यूएसएआईडी की शुरुआत की थी। इसका वार्षिक बजट 40 अरब डॉलर से ज्यादा है। फिलहाल ट्रंप ने इस पर तीन महीने की रोक लगा दी है। समीक्षा के बाद इसके तहत होने वाली कुछ फंडिंग को फिर से शुरू किया जा सकता है।

इयाल जमीर बने इजराइली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ

तेल अवीव, एजेंसी। इजराइली सरकार ने रविवार को मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) इयाल जमीर को इजराइली रक्षा बलों के अगले चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। जमीर लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी की जगह लेंगे, जिन्होंने 21 जनवरी को घोषणा की थी कि वे सेना की 7 अक्टूबर की विफलताओं के कारण इस्तीफा दे देंगे। हलेवी 5 मार्च को पद छोड़ने वाले हैं।

जमीर, 59, का जन्म और पालन-पोषण इलात में हुआ। वे आर्मर्ड चीफ में अपना करियर शुरू करने के लिए चीफ ऑफ स्टाफ बनें। 1984 में सेना में शामिल होने के बाद वे एक टैंक कमांडर बन गए, धीरे-धीरे रैंक चढ़ते गए। आधिकारिक तौर पर 2012-2015 तक नेतन्याहू के सैन्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। वाशिंगटन स्थित वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर निरय ईस्ट पॉलिसी में इंडस्ट्रियल रिसर्च फेलो बने से पहले 2018 से 2021 तक वे डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ थे।

जमीर को 2018 और 2022 में चीफ ऑफ स्टाफ के लिए भी विचार किया गया था। 2023 में, उन्हें रक्षा मंत्रालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया। उनके पास तेल अवीव और हाइफा विश्वविद्यालयों से



भी डिग्री है और वे व्हाटन विश्वविद्यालय के सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम के स्नातक हैं। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ तीन साल के लिए काम करता है, जिसमें एक साल का विस्तार भी संभव है। अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद छोड़ने वाले आखिरी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट-जनरल थे।

लेन हल्टरुज, जिन्होंने 2006 के दूसरे उभयतंत्र युद्ध के दौरान आईडीएफ की विफलताओं के कारण 2007 में इस्तीफा दे दिया था। राजनीतिक और सैन्य विफलताओं की जांच के लिए सरकार द्वारा एक स्वतंत्र जांच आयोग नियुक्त करने की मांग बढ़ रही है। ऐसे आयोगों के पास गवाहों को बुलाने और सबूत इकट्ठा करने का व्यापक अधिकार होता है और इनका नेतृत्व

सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ न्यायाधीश करते हैं। इनमें जांच के दायरे में आने वाले व्यक्तियों के बारे में व्यक्तिगत सिफारिशें शामिल हो सकती हैं, हालांकि सरकार विस्तार भी संभव है। अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद छोड़ने वाले आखिरी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट-जनरल थे।

नेतन्याहू और सत्तारूढ़ गठबंधन का कहना है कि एक स्वतंत्र आयोग की नियुक्ति युद्ध के बाद ही की जानी चाहिए। पिछले राज्य जांच आयोग ने, जिसने इजराइल की सबसे खराब नागरिक आपदा (मेरोन पर्वत पर एक पवित्र स्थल पर भगदड़ जिसमें 45 लोग मारे गए थे) की जांच की थी, अप्रैल में जारी एक रिपोर्ट में नेतन्याहू को इस त्रासदी के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया था।

ट्रंप ने हटाए प्रतिबंध, इजराइल पहुंची अमेरिकी बमों की बड़ी खेप

यरूशलम, एजेंसी। अमेरिका और इजराइल के बीच संबंधों में काफी बदलाव आए हैं। ये बदलाव डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद हुआ है। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन द्वारा इजराइल को हथियारों की आपूर्ति करने पर लगाई गई रोक को पलट दिया। इस फैसले के बाद अमेरिका ने इजराइल को एमके-84 जैसे भारी बमों की आपूर्ति की है। हालांकि, इस समय इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम लागू है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका द्वारा हाल ही में हथियारों की आपूर्ति पर लगी रोक को हटा लिया गया है। इसके बाद इजराइल को अमेरिकी एमके-84 बमों की आपूर्ति की गई। एमके-84 एक विशेष प्रकार का बम है जो लक्ष्यों को भेदने और अपनी भारी विस्फोट शक्ति से व्यापक क्षति पहुंचाने में सक्षम है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने रविवार को एक बयान में कहा कि हथियारों की यह खेप शनिवार देर रात इजराइली बंदरगाह अशदोद पहुंची और इसे रात भर में उतार कर गतव्य तक पहुंचा दिया गया।

समाचार एजेंसी सिन्हूआ के अनुसार मंत्रालय द्वारा जारी वीडियो फुटेज में शिपिंग कटेनरों को दर्जनों ट्रकों पर लादते हुए दिखाया गया। मंत्रालय के अनुसार बमों को इजराइल की वायु सेना के टिकानों तक पहुंचाया गया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने



गाजा पट्टी के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में उनके संभावित उपयोग और प्रभाव के बारे में चिंताओं के कारण इजरायल को एमके-84 बमों की डिलीवरी को निलंबित कर दिया था।

गाजा में अक्टूबर 2023 से इजरायली बमबारी और जमीनी हमलों में हजारों लोग मारे गए। इसी बयान में इजराइली रक्षा मंत्री इजरायल काटज़ ने कहा कि लेटेस्ट शिपमेंट वायुसेना और आईडीएफ (इजरायल रक्षा बलों) के लिए एक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन को बमों की आपूर्ति करने और इजरायल के प्रति उनके अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। इजरायल के रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 7 अक्टूबर, 2023 को गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से, 678 एयरलिफ्ट और 129 समुद्री शिपमेंट के माध्यम से 76,000 टन से अधिक सैन्य उपकरण इजरायल पहुंचे हैं।

हमास का सफाया किया जाना चाहिए, गाजा में अस्थिर युद्धविराम पर संदेह और बढ़ा : रुबियो

यरूशलम, एजेंसी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने गाजा पट्टी में इजराइल के युद्ध उद्देश्यों का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि हमास को 'खत्म किया जाना चाहिए' क्योंकि इसने अस्थिर युद्धविराम के भविष्य पर संदेह खड़ा कर दिया है। रुबियो ने क्षेत्रीय दौरे की शुरुआत में यरूशलम में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की, जहां उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पट्टी से फलस्तीनी आबादी को स्थानांतरित करने और अमेरिकी स्वामित्व के तहत इसे पुनर्विकसित करने के प्रस्ताव पर अरब नेताओं से प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है।

नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और कहा कि गाजा के भविष्य के लिए उनके व ट्रंप के पास एक 'साझा रणनीति' है। नेतन्याहू ने ट्रंप की बात दोहराते हुए कहा कि अगर हमास सात अक्टूबर 2023 को किये हमले में अपहृत दर्जनों



बंधकों को रिहा नहीं करता है, तो 'नरक के द्वार खुल जायेंगे'। इजराइल के प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी युद्धविराम के पहले चरण के समाप्त होने से ठीक दो सप्ताह पहले आई है। दूसरे चरण पर हालांकि अब तक बातचीत नहीं हुई है, जिसमें

हमास को अधिक फलस्तीनी कैदियों के बदले में दर्जनों शेष बंधकों को रिहा करना है। रुबियो ने गाजा के हमास 'सैन्य या सरकारी बल के रूप में मौजूद नहीं रह सकता'। रुबियो ने कहा, जब तक यह (हमास) शासन-प्रशासन के रूप में एक

ताकत बनकर खड़ा है तब तक शांति असंभव है। इसे मिटा दिया जाना चाहिए।

इस तरह की हमास के साथ बातचीत जारी रखने के प्रयासों को जटिल बना सकती है, जो युद्ध में भारी नुकसान उठाने के बावजूद कायम है और गाजा पर इसका नियंत्रण बरकरार है। इस बीच इजराइली सेना ने बताया कि उसने रविवार तड़के दक्षिणी गाजा में उसकी सेना के पास आने वाले लोगों पर हवाई हमला किया। हमास द्वारा संचालित आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि हमला उस समय हुआ जब पुलिसकर्मी मिस्त्र की सीमा पर राफा के पास सहायता ट्रकों के प्रवेश को सुरक्षित कर रहे थे। मंत्रालय के मुताबिक, हमले में तीन पुलिसकर्मीयों की मौत हो गयी।

गाजा में इजरायल की नीतियों का स्पष्ट समर्थन करने के लिए अमेरिका का धन्यवाद करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि उनकी और ट्रंप की

एक समान रणनीति है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि हम हमेशा इस रणनीति का विवरण सार्वजनिक नहीं कर सकते, जिसमें यह भी शामिल है कि हम कब कड़े कदम उठाएंगे, क्योंकि हम तब तक ऐसा करेंगे जब तक हमारे सभी बंधक रिहा नहीं हो जाते।

नेतन्याहू ने ईरान के मामले में अमेरिका-इजरायल समन्वय पर भी जोर दिया। कहा कि दोनों देश तेहरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों का सामना करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए और क्षेत्र में ईरान का आक्रामकता को रोकना होगा। रुबियो ने अपनी टिप्पणी में कहा कि गाजा में अभी भी बंधक बनाए गए लोगों को घर लौटने की जरूरत है, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए।

संक्षिप्त खबरें

ट्रेनों के परिचालन में बदलाव

हाजीपुर(बिभा) : तकनीकी कारणों से निम्नालिखित ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है - रद्द ट्रेनें - 18 एवं 21 फरवरी, 2025 तक नई दिल्ली से खुलने वाली 12802 नई दिल्ली-पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस । 19 फरवरी, 2025 को बीकानेर से खुलने वाली 22308 बीकानेर-हावड़ा एक्सप्रेस एवं दिनांक 20 एवं 21 फरवरी, 2025 को बीकानेर से खुलने वाली 12308 बीकानेर-हावड़ा एक्सप्रेस । 18 एवं 21 फरवरी, 2025 तक कालका से खुलने वाली 12312 कालका-हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस । 18, 20 एवं 21 फरवरी, 2025 को जम्मूतवी से खुलने वाली 18310 जम्मूतवी-संबलपुर एक्सप्रेस । 19 फरवरी, 2025 को जम्मूतवी से खुलने वाली 18102 जम्मूतवी-टाटा एक्सप्रेस । 18 एवं 21 फरवरी, 2025 तक नई दिल्ली से खुलने वाली 12368 नई दिल्ली-भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस । 19 फरवरी, 2025 को आनंद विहार से खुलने वाली 22466 आनंद विहार-मधुपुर एक्सप्रेस । 19 एवं 21 फरवरी, 2025 को अहमदाबाद से खुलने वाली 19483 अहमदाबाद-बरीनी एक्सप्रेस । 21 एवं 23 फरवरी, 2025 को बरीनी से खुलने वाली 19484 बरीनी-अहमदाबाद एक्सप्रेस । 18 फरवरी, 2025 को ग्वालियर से खुलने वाली 12176 ग्वालियर-हावड़ा एक्सप्रेस । दिनांक 18 एवं 20 फरवरी, 2025 को इंदौर से खुलने वाली 22911 इंदौर-हावड़ा एक्सप्रेस । 20 फरवरी, 2025 को आगरा कैंट से खुलने वाली 20976 आगरा कैंट-हावड़ा चंबल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलायी जाने वाली ट्रेनें - मानिकपुर-प्रयागराज छिक्की-जीवनथपुर-वाराणसी-जौनपुर-औड़िहार के रास्ते चलायी जाने वाली ट्रेनें - 18 से 28 फरवरी, 2025 तक लोकमान्य तिलक टर्मिनल से खुलने वाली 11061 लोकमान्य तिलक-जयनगर एक्सप्रेस । 18 से 27 फरवरी, 2025 तक जयनगर से खुलने वाली 11062 जयनगर-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस । 19 एवं 26 फरवरी, 2025 को पुणे से खुलने वाली 11033 पुणे-दरभंगा एक्सप्रेस । 21 से 28 फरवरी, 2025 को दरभंगा से खुलने वाली 11034 दरभंगा-पुणे एक्सप्रेस । कानपुर-लखनऊ-गोरखपुर-छपरा के रास्ते चलायी जाने वाली ट्रेनें - 18 से 21 फरवरी, 2025 तक दिल्ली से खुलने वाली 15657 दिल्ली-कामाख्या एक्सप्रेस । 18 से 21 फरवरी, 2025 तक आनंद विहार से खुलने वाली 12506 आनंद विहार-कामाख्या एक्सप्रेस । 19 फरवरी, 2025 को बीकानेर से खुलने वाली 15633 बीकानेर-गुवाहाटी एक्सप्रेस । कानपुर-लखनऊ-डीडीयू के रास्ते के रास्ते चलायी जाने वाली ट्रेन - दिनांक 19 एवं 26 फरवरी, 2025 को आनंद विहार से खुलने वाली गाड़ी सं. 12330 आनंद विहार-सियालदह एक्सप्रेस । डीडीयू-वाराणसी-जंघई-उन्नाव-कानपुर के रास्ते के रास्ते चलायी जाने वाली ट्रेन - दिनांक 18 एवं 25 फरवरी, 2025 को सियालदह से खुलने वाली गाड़ी सं. 12329 सियालदह-आनंद विहार एक्सप्रेस ।

रेलकर्मियों ने महाप्रबंधक से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से कराया अवगत



हाजीपुर(बिभा) : हाजीपुर में 04 रेलकर्मियों/उनके आश्रितों ने पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री छत्रसाल सिंह से मुलाकात की तथा अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया । महाप्रबंधक ने संबंधित विभागों को प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में केस निष्पादन के निर्देश दिए । रेलकर्मियों एवं उनके आश्रितों की विभागीय समस्याओं के निष्पादन के उद्देश्य से महाप्रबंधक से मुलाकात हेतु प्रत्येक मंगलवार का दिन निर्धारित किया गया है । इसके लिए रेलकर्मियों अपना नाम पूर्व में कार्मिक विभाग में पंजीकृत करवाकर मंगलवार को महाप्रबंधक से मुलाकात कर अपनी समस्याएं उनके सामने रख सकते हैं ।

भारतीय रेलवे की पृथ्वी के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका

बिभा संवाददाता

प्रयागराज : प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में अब तक 53 करोड़ पवित्र स्नान कर चुके हैं, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम बन गया है । प्रतिदिन लाखों भक्तों के आने के साथ, भारतीय रेलवे तीर्थयात्रियों के सुगम एवं निर्बाध आवागमन के बेहतर प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ।

भारतीय रेल द्वारा महाकुंभ क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर पिछले 03 वर्षों में विभिन्न यात्री सुविधाओं के उन्नयन हेतु 5,000 करोड़ की लागत बड़े पैमाने पर लाजिस्टिक प्रयास किया गया है ताकि सभी यात्रियों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित किया जा सके । इसमें रेलवे स्टेशनों का उन्नयन, 13,000 से अधिक ट्रेनें चलाने की योजना और उन्नत भीड़ प्रबंधन प्रणाली शामिल हैं । भारतीय रेलवे इस भव्य आध्यात्मिक आयोजन को किस तरह से सुविधाजनक बना रहा है, इस पर एक नजर -

महाकुंभ 2025 के लिए बड़ी संख्या में ट्रेनों का परिचालन -

निर्बाध यात्रा के लिए ट्रेनों का डायवर्जन - यात्री आवागमन को प्राथमिकता देने के



लिए सभी मालगाड़ियों को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर डायवर्ट किया गया है । शॉर्टिंग संचालन से बचने के लिए दोनो तरफ ट्रेन सेट या इंजन के साथ 200 रोक तैनात किए गए हैं ।

ट्रेन सेवाओं की अशूतपूर्ण संख्या -

26 फरवरी 2025 तक 13,000 ट्रेनों के परिचालन की योजना बनाई गई थी, जिनमें से 16 फरवरी 2025 तक 12,583 ट्रेनें पहले ही चल चुकी हैं । भारतीय रेलवे अधिकतम यात्री सेवा को संभाल रहा है - 13 जनवरी 2025 से, भारतीय रेलवे ने प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में 3.09 करोड़ तीर्थयात्रियों को अपनी सेवाएं दी हैं । 17 फरवरी को 18.60 लाख यात्री और 16 फरवरी 2025 को 18.48 लाख यात्रियों ने यात्रा की, जो पिछले दो दिनों में यात्रियों की सबसे अधिक आवाजाही में से एक है ।

अन्य महत्वपूर्ण तिथियां जिस दिन बड़ी संख्या में यात्रियों ने ट्रेन सेवा का उपयोग किया -

दाखिल खारिज के मामलों को निर्धारित अवधि में निष्पादन नहीं करने पर उपायुक्त ने की बड़ी कार्रवाई नीलांबर-पीतांबरपुर के सीओ, सीआई एवं कर्मचारी पर लगा 65-65 हजार का अर्थदंड

बिभा संवाददाता

मेदिनीनगर (पलामू) : दाखिल खारिज के मामलों को लंबित रखने को लेकर पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने कड़ी नाराजगी जताई है । उन्होंने दाखिल खारिज के मामलों को निर्धारित अवधि में निष्पादन नहीं करने के बजाए लंबित रखने को लेकर नीलांबर-पीतांबरपुर के अंचल अधिकारी सहित तीन के विरुद्ध आज कार्रवाई की है । उन्होंने नीलांबर-पीतांबरपुर के अंचल अधिकारी सुनील कुमार सिंह, कर्मचारी/राजस्व उप निरीक्षक रिशेरा रंजन तिवारी एवं प्रभारी सीआई महेंद्र राम के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 65-65 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है । अर्थदंड की राशि संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों के वेतन से कोषागार द्वारा कटौती की जाएगी ।



इनके विरुद्ध आरोप है कि दाखिल खारिज के लिए प्राप्त आवेदनों का समय निष्पादन नहीं किया । जबकि इसके लिए वरीय अधिकारियों का भी निर्देश प्राप्त हुआ । दाखिल खारिज के 62 मामलों नामांतरण करने की निर्धारित तिथि से अधिक समय तक लंबित रखने गये, जबकि सामान्य तौर पर 30 दिनों के अंदर दाखिल खारिज के मामलों का

नामांतरण किया जाना है तथा आपत्ति के मामलों में 90 दिनों के अंदर नामांतरण करने का समय निर्धारित है । तीनों के विरुद्ध झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है । उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि पलामू वासियों को कठिनाई नहीं हो, इसके लिए प्रशासन सक्रिय रूप से कार्य कर रही है । विकास

कार्यों की गति को स्थिरीकरण करने वालों के विरुद्ध आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी ।

अपर समाहर्ता ने दी थी चेतावनी

दाखिल खारिज के मामलों का समय निष्पादन हेतु पलामू के अपर समाहर्ता द्वारा भी चेतावनी दी गई थी । विदित हो कि अपर समाहर्ता द्वारा 21 दिसंबर 2024 को कार्यालय का निरीक्षण के दौरान मामलों का समय निष्पादन का निर्देश दिया गया था । इसके बावजूद निष्पादन नहीं होने की स्थिति में अपर समाहर्ता द्वारा 8 फरवरी 2025 को बैठक के क्रम में चेतावनी दी गई थी । इसके बावजूद भी इन 62 मामलों का निष्पादन समय नहीं किया गया ।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा को लेकर जसीडीह व मधुपुर रेलवे स्टेशन का अनुमंडल पदाधिकारी ने किया निरीक्षण

बिभा संवाददाता

देवघर : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री विशाल सागर के निदेशानुसार जिले से महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ महाशिवरात्रि को लेकर देवघर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा से रेल परिवहन पर बढ़े दबाव के मद्देनजर किए गए कार्यों का निरीक्षण अनुमंडल पदाधिकारी देवघर श्री रवि कुमार द्वारा जसीडीह जंक्शन व अनुमंडल पदाधिकारी मधुपुर श्री राजीव कुमार द्वारा मधुपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया । साथ ही रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा और सुरक्षाओं व्यवस्था के अलावा भीड़ नियंत्रण के इंतजाम, यातायात व्यवस्था, पार्किंग की सुविधा एवं अन्य



आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया गया, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो । इसके अलावा महाकुंभ व महाशिवरात्रि के श्रद्धालुओं एवं अन्य यात्रियों के लिए यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय लागू करने का निर्देश दिया गया है, ताकि सभी रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम रेलवे

स्टेशन पर रहे । इसके अलावा जसीडीह जंक्शन और मधुपुर जंक्शन परिसर व स्टेशन में साफ-सफाई के अलावा ट्रेन आगमन के समय यात्रियों को ट्रेन से उतरने या चढ़ने में किसी प्रकार की समस्या न हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखने का निर्देश रेलवे स्टेशन के अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया ।

रेलवे स्टेशन पर काउंट मैनेजमेंट हेतु प्लेटफार्म पर आरपीएफ को विशेष टीम रहेगी तैनात

जसीडीह व मधुपुर रेलवे जंक्शन से देश के कई राज्यों के लिए प्रतिदिन करीब डेढ़ सौ ट्रेनें परिचालित होती हैं । वर्तमान में प्रतिदिन 10 एसी ट्रेनें जसीडीह स्टेशन से गुजरती हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों से आती हैं और जसीडीह होते हुए महाकुंभ प्रयागराज पहुंचती हैं । महाकुंभ को देखते हुए जसीडीह रेलवे स्टेशन पर होने वाली अत्यधिक भीड़ को लेकर हर शिफ्ट में रेलवे पुलिस के कर्मचारी उपस्थित रहेंगे । साथ ही जिस प्लेटफार्म से महाकुंभ के लिए ट्रेन रवाना होती है, उस प्लेटफार्म पर आरपीएफ की विशेष टीम तैनात की गई है ।

उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला खनिज न्यास संस्थान की हुई बैठक

सिमडेगा : उपायुक्त सिमडेगा श्री अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला खनिज न्यास संस्थान सिमडेगा की न्यास परिषद की बैठक हुई । बैठक के दौरान डीएमएफटी प्रबंधकीय समिति की बैठक में डीएमएफटी मद ने नए प्रोजेक्ट पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने जनिहित से जुड़ी तथा प्राथमिकता क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं महिला एवं बाल विकास आदि से संबंधित कार्यों योजनाओं की क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत दी । जिसमें सदर अस्पताल सिमडेगा में अल्ट्रासाउंड मशीन की खरीद एवं संचालन करने, शिक्षा विभाग अंतर्गत कुल 06 विद्यालय में शौचालय निर्माण करने एवं 10 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने, कोलेबिरा, बानो एवं बोलबा कस्त्रबा गांधी आवासीय विद्यालय में पानी की समस्या को दूर करने हेतु नये बोरिंग कराने, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बानो में पहुंच पथ निर्माण करने हेतु प्रस्ताव अनुमोदन दिया गया । इसके अलावे खनिज प्रभावित क्षेत्र के पीटो हो खेल विकास योजना में खेल मैदान पर वेंजिंग रूम -सह- शौचालय निर्माण से संबंधित प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन दिया गया ।

बाबा मंदिर प्रांगण स्थित सभी दानपात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया

देवघर (बिभा) : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर द्वारा जानकारी दी गई कि मंगलवार को बाबा मंदिर प्रांगण स्थित 18 दानपात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया । साथ ही गिनती के पश्चात दानपात्र से कुल आय 9,85,887 रुपए के अलावा नेपाली नगद - 1,160, कर्नेडियन डॉलर - 50 दान स्वरूप प्राप्त हुआ । इससे अलावे मंदिर के दान पात्र को कड़ी सुरक्षा के बीच खोला गया । पात्र से निकले पैसे को गिनती के लिए मंदिर प्रशासनिक भवन में रखा गया । ज्ञात हो कि इससे पूर्व 16 जनवरी को मंदिर प्रांगण के सभी दानपात्रों को खोला गया था ।

St. ARVINDO ACADEMY

Affiliated to C.B.S.E (Delhi)

Anuj Kumar Sahu
(President)

Other Facility

Bus Available

computer Lab

Laboratory

Library

BEHIND ARGORA HOUSING COLONY, MAHAVIR NAGAR, ARGORA, RANCHI (JHARKHAND)

www.starvindoacademy.org

Contact No. : 8252799128, 9431358509, 0651-3555455